RNI No. DLHIN/25/A2321

DD

दिव्य दिल्ली

दिल्ली से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र

वर्ष: 01, अंक: 10, पृष्ठ: 08 infodivyadelhi@gmail.com

रविवार, 07 सितम्बर, 2025 तदनुसार 19 भाद्रपद विक्रमी सम्वत 2082 | www.divyadelhi.com | facebook.com/divyadelhi तापमान अधिकतम 30 डिग्री न्यूनतम 25 डिग्री सूयोदय 05.25 | सूर्यास्त 06.50

डैमेज कंट्रोल में ट्रंप, मोदी ने भी बढ़ाया दोस्ती का हाथ

भारत चीन और अमेरिका दोनों के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है

राजेश चौहान
नई दिल्ली

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें अपना दोस्त और एक महान प्रधानमंत्री कहा था। ट्रंप के इस बयान पर पीएम मोदी ने भी प्रतिक्रिया दी और अमेरिकी राष्ट्रपति को धन्यवाद कहते हुए भारत-अमेरिका को वैश्विक साझेदार बताया है। पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में कहा कि वे ट्रंप की भावनाओं और संबंधों के सकारात्मक आकलन की गहराई से सराहना करते हैं और पूरी तरह से प्रत्युत्तर देते हैं। उन्होंने लिखा कि भारत और अमेरिका के बीच एक सकारात्मक और भविष्य उन्मुख व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदार है।

जब से ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है तभी से भारत ने बेहद संतुलित और परिपक्व रुख अपनाया है। ट्रंप के विवादित और कभी-कभी कठोर बयानों पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि मौन और तर्क के आधार पर अपनी स्थिति स्पष्ट की। प्रधानमंत्री मोदी ने भी संवेदनशीलता और संयम दिखाते हुए बयान दिए, जो तथ्यात्मक और शांतिपूर्ण रहे। भारत का रुख यह रहा कि अमेरिका के साथ उसकी रणनीतिक साझेदारी अहम है, लेकिन अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखना भी उतना जरूरी है।

अमेरिका के साथ बातचीत चल रही: जयशंकर

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका रिश्ते अब भी बने हुए हैं। दोनों देश लगातार बातचीत कर रहे हैं। उनका यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान के बाद आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत और अमेरिका के रिश्ते दूरदर्शी हैं। भारत और अमेरिका के बीच वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति के उस बयान का जवाब दे रहे थे, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं हमेशा नरेंद्र मोदी का दोस्त रहूंगा, वह एक महान प्रधानमंत्री हैं। भारत और अमेरिका के बीच एक खास रिश्ता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से भारत-अमेरिका संबंधों पर सकारात्मक बात कहने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिक्रिया पर विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा, 'पीएम मोदी अमेरिका के साथ हमारी साझेदारी को बहुत महत्व देते हैं।

भारत है मजबूत साझेदार

वैश्विक परिदृश्य में भारत चीन और अमेरिका दोनों के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। चीन चाहता है कि भारत उसके साथ जुड़कर क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाए, जबकि अमेरिका भारत को मजबूत साझेदार के रूप में देखता है। हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री और अमेरिकी दूतावास ने सितंबर महीने को भारत-अमेरिका के संबंधों को और बेहतर बनाने का महीना घोषित किया और लोगों से इस पहल में समर्थन का आह्वान किया। यह कदम दोनों देशों के बीच संपर्क बढ़ाने और सकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश के रूप में देखा गया।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ?

विशेषज्ञ रविंद्र सचदेवा कामानना है कि ट्रंप के शुरूआती बयान भावनात्मक होते हैं, लेकिन बाद में वे पुनर्विचार करते हैं। उन्होंने कहा कि एससीओ समिट में भारत, चीन और रूस के नेताओं की एक साथ मौजूदगी और परेड प्रदर्शन ने शायद ट्रंप को महसूस कराया कि भारत रूस और चीन के करीब जा रहा है। इसी वजह से उन्होंने शुरूआत में भारत और रूस को खो देने जैसी टिप्पणी की थी।

मोदी नहीं जाएंगे अमेरिका, विदेश मंत्री जयशंकर करेंगे यूएन महासभा को संबोधित

नई दिल्ली। भारत और अमेरिकि में खटास की खबरों के बीच एक बड़ी जानकारी सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका जाने वाले थे, लेकिन अब वो इस बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। उनकी जगह विदेश मंत्री एस.जयशंकर इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक पर संशोधित सूची में यह जानकारी सामने आई है। 9 सिंतबर से बैठक का 80वां सत्र शुरू होगा। वहीं, 23-29 सिंतबर तक यूएन में उच्चस्तरीय बैठक देखने को मिलेगी। इस बैठक की शुरूआत ब्राजील के भाषण से होगी।

देश की सुरक्षा सिर्फ सैनिकों का काम नहीं..

देश की सुरक्षा सिर्फ सैनिकों का काम नहीं है बल्कि ये हर नागरिक की जिम्मेदारी है: आर्मी चीफ

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 72,000 से ज्यादा एनसीसी जवान थे

नई दिल्ली

आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एक बयान में कहा है कि देश की सुरक्षा सिर्फ सैनिकों का काम नहीं है बल्कि ये हर नागरिक की जिम्मेदारी है। आर्मी चीफ ने कहा 'नागरिक ही सैनिकों को सबसे पहले सूचना देते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 72,000 से ज्यादा एनसीसी जवान थे, जिन्होंने ऑपरेशन के दौरान सभी जरूरी सहायता प्रणालियों का नेतृत्व किया और नागरिक की सुरक्षा के लिए निस्वार्थ भाव से काम किया। यूक्रेन ने दुनिया को दिखाया है कि जब आम नागरिक अपने देश की रक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं तो क्या होता है। उनकी भूमिका खुफिया जानकारी जुटाने, रसद और प्रतिरोध में साबित हुई है। इससे पता चलता है कि देश की सुरक्षा सिर्फ सैनिकों का काम नहीं है, बल्कि ये सभी की जिम्मेदारी है।' गोरखपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा कि बालाकोट एयरस्ट्राइक के बाद भारत और पाकिस्तान ने अलग-अलग सबक सीखे।

पंजाब: चार फीट भरा पानी, जलभराव में रहने को मजबूर

अमृतसर

पंजाब के अमृतसर के अजनाला के सीमांत ब्लॉक रमदास का गांव साहूवाल बाढ़ से बेहाल है। पूरा गांव पानी में डूबा है। हालात दयनीय बने हुए हैं। इससे वहां काफी नुकसान हुआ है। लोग कई दिनों से पानी के बीच ही रहने को मजबूर हैं। इससे गांव में बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। रावी दरिया में आई बाढ़ का चार-चार फीट तक पानी भरा है। लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही।

गांव साहूवाल के हालात इस बात की गवाही देते हैं कि आपदा केवल प्राकृतिक नहीं बल्कि सामाजिक-आर्थिक समस्याओं को भी जन्म देती है। यहां के लोग अभी तक बाढ़ की समस्याओं से दो-दो हाथ कर रहे हैं।

राहत और बचाव कार्य जारी है लेकिन ग्रामीणों की असली लड़ाई अब आजीविका बहाली, स्वास्थ्य और पुनर्निर्माण की है। जब तक सरकार और प्रशासन ठोस कदम नहीं उठाते तब तक साहूवाल के लोगों को इन्हीं मुश्किलों से दो चार होना पड़ेगा। गांव के लोगों जसपाल सिंह, हरदीप सिंह, मंगा सिंह और हरजिंदर ने बताया कि पानी का स्तर कुछ कम हुआ है लेकिन बीमारियों का खतरा बढ़ गया है।

प्रशासन की टीमों ने मेडिकल किटें बांटी

गांव में लोगों को बुखार की शिकायत बढ़ रही है। प्रशासन की टीमों ने मेडिकल किटें बांटी हैं लेकिन जांच की पूरी सुविधा न होने से लोग अब भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।

पशुओं पर आफत

साहूवाल के लोगों को मवेशियों की भी चिंता सता रही है। चारे की भारी कमी से पशु भूखे हैं। लगातार पानी में रहने से उनके पैरों में संक्रमण फैल रहा है।

अब तक चार ग्रामीणों को सर्पदंश का सामना करना पड़ा लेकिन मौके पर मेडिकल सहायता उपलब्ध होने से उनकी जान बच गई।

सहकारिता क्षेत्र में जीएसटी की कटौती से दूध, ट्रैक्टर, उर्वरक होंगे सस्ते

लोगों को बड़ी राहत: थर्ड-पार्टी बीमा और लॉजिस्टिक्स जैसी तमाम चीजों की लागत घटेगी

नई दिल्ली

केंद्र सरकार के सहकारिता क्षेत्र में सहकारी संस्थाओं, किसानों और ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में कटौती के फैसले से 10 करोड़ से अधिक डेयरी किसानों को सीधा फायदा होगा। सरकार के डेयरी क्षेत्र में दी गई रियायतों से दुग्ध उत्पादन, ट्रैक्टरों और उनके पुर्जों, थर्ड-पार्टी बीमा और लॉजिस्टिक्स जैसी तमाम चीजों की लागत घटेगी, जिससे ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा और आम लोगों को महंगी कीमतों से राहत मिलेगी। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार, दूध और पनीर पर जीएसटी पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। जबकि मक्खन, घी और दूध के कनस्तरों पर जीएसटी 12 फीसदी से घटा कर 5 फीसदी किया गया है। खाद्य पदार्थों जैसे चीज, नमकीन, पास्ता, जैम, जेली और जूस पर भी जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है। इसके अलावा, ट्रैक्टर, उर्वरक, बायो-पेस्टीसाइड और मालवाहक वाहनों पर भी जीएसटी कम किया गया है, जिससे खेती, दुग्ध उत्पादन और लॉजिस्टिक्स लागत घटेगी। ये कदम सहकारी क्षेत्र को मजबूत करेंगे, ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देंगे और आम लोगों के लिए जरूरी वस्तुएं सस्ती करेंगे। दूध और पनीर को जीएसटी से मुक्त करने से दुग्ध सहकारिताओं को बड़ा फायदा होगा। मक्खन और घी पर 5 फीसदी जीएसटी से दुग्ध उत्पाद सस्ते होंगे, जिससे उपभोक्ताओं को पोषण सुरक्षा मिलेगी और दुग्ध किसानों की आय बढ़ेगी। खासकर महिला-नेतृत्व वाली ग्रामीण उद्यमशीलता और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को इससे बल मिलेगा। खाद्य प्रसंस्करण में भी राहत दी गई है। चॉकलेट, कॉर्न फ्लेक्स, आइसक्रीम, बिस्किट और कॉफी जैसे उत्पादों पर जीएसटी 18 फीसदी से घटा कर 5 फीसदी किया गया है। इससे ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में मांग बढ़ेगी और खाद्य प्रसंस्करण सहकारिताएं मजबूत होंगी। पैकिंग पेपर और डिब्बों पर भी जीएसटी 5 फीसदी कर दिया गया है, जिससे पैकेजिंग लागत कम होगी।

ट्रैक्टर सस्ते होंगे, जिसका फायदा किसानों को मिलेगा

कृषि क्षेत्र में 1800 सीसी से कम क्षमता वाले ट्रैक्टरों और उनके पुर्जों पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया गया है। इससे ट्रैक्टर सस्ते होंगे, जिसका फायदा फसल उत्पादन, पशुपालन और चारे की ढुलाई में लगे किसानों को मिलेगा। उर्वरक उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले अमोनिया, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल पर भी जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया गया है, जिससे उर्वरक सस्ते होंगे और किसानों को राहत मिलेगी। बायो-पेस्टीसाइड और सूक्ष्म पोषक तत्वों पर जीएसटी 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने से जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा, मिट्टी की सेहत सुधरेगी और छोटे किसानों व एफपीओ को फायदा होगा। वाणिज्यिक वाहनों में ट्रक और डिलीवरी वैन पर जीएसटी 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी किया गया है।

मालवाहक वाहनों के थर्ड-पार्टी बीमा पर जीएसटी 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने के साथ इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा भी दी गई है। इससे ढुलाई लागत कम होगी, कृषि उत्पादों का परिवहन सस्ता होगा और निर्यात में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।

जीएसटी में सुधार से 140 करोड़ देशवासियों को बड़ी राहत: अश्विनी

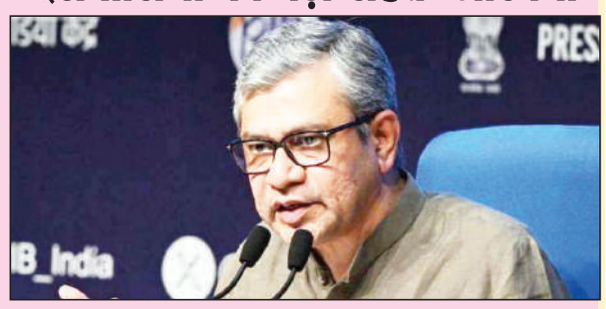

नई दिल्ली

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधारों को 140 करोड़ देशवासियों के लिए बड़ी राहत पहुंचाने वाला बताया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) मुख्यालय में शनिवार को पत्रकार वार्ता में वैष्णव ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मध्यम वर्ग के प्रति काफी निष्ठा है जो समय-समय पर हम सभी को दिखाई देती है। उन्होंने करों में बड़ा सुधार करके 12 लाख रुपये तक की आय वाले मध्यम वर्गीय परिवारों को छूट देकर और अब बड़े पैमाने पर जीएसटी में सुधार करके मध्यम वर्ग के परिवारों को बड़ी राहत और तोहफा दिया है।" उन्होंने कहा कि जीएसटी में जिस तरह के सुधार हुए हैं उनसे देश के 140 करोड़ देशवासियों को बड़ी राहत मिली है। काग्रेस पर निशाना साधते हुए वैष्णव ने कहा कि 2014 से पहले करों का मकड़जाल फैला था जिसके कारण हर वस्तु पर कई तरह के कर लगाकर एक साधारण परिवार , आम आदमी और मध्यम वर्गीय परिवार पर बड़ा बोझ डाल दिया गया था। मंत्री ने कहा, आज जीएसटी में सुधार से देश के जन-जन पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा और उन्हें राहत मिलेगी। जरुरत की सारी वस्तुओं पर जीएसटी कम किया गया है। इससे रोटी, कपड़ा और मकान तीनों पर करों का बोझ कम हुआ है। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा, "आज इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की कई तरह की चीजें हर घर में उपयोग में लाई जाती हैं और सोलर पैनल से लेकर मोबाइल फोन जैसी वस्तुओं पर जिसतरह से जीएसटी करों में सुधार हुआ है उससे इन वस्तुओं पर खर्च से लोगों को राहत मिलेगी।"

मुख्य न्यायाधीश गवई ने भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुंबिनी का दौरा किया

काठमांडू

भारत के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई ने नेपाल में आज भगवान गौतम बुद्ध की पवित्र जन्मस्थली लुम्बिनी की यात्रा की। न्यायपालिका का सर्वोच्च दायित्व संभालने के बाद यह उनकी पहली नेपाल यात्रा है। उन्होंने लुम्बिनी आगमन को एक विशेष आध्यात्मिक अवसर बताया है। शनिवार सुबह लुम्बिनी में आने वाले गवई का लुम्बिनी विकास ट्रस्ट के उपाध्यक्ष डॉ. ल्हारकयाल लामा, सदस्य सचिव सनुराजा शाक्य, कार्यकारी सदस्य श्याम रोक्का, वरिष्ठ प्रशासन प्रमुख ज्ञानिन राय और ट्रस्ट के अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्वागत किया। यात्रा के दौरान, गवई ने लुम्बिनी क्षेत्र के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के बारे में जाना। उन्होंने मायादेवी मंदिर परिसर का दौरा किया, बुद्ध की जन्मस्थली का अवलोकन किया और सूत्र का पाठ किया। उन्होंने विश्व शांति, मानव कल्याण, नेपाल की प्रगति और भारत-नेपाल के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत करने की कामना करते हुए दीप प्रज्वलित किया। लुम्बिनी की अपनी यात्रा के बाद, गवई ने लुम्बिनी विकास कोष के अधिकारियों के साथ मास्टर प्लान और वर्तमान में चल रही विकास और निर्माण गतिविधियों का अवलोकन किया । उन्होंने लुम्बिनी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए नेपाल के प्रयासों की सराहना की तथा विश्वास व्यक्त किया कि इस क्षेत्र में भारत का सहयोग जारी रहेगा। मुख्य न्यायाधीश गवई नेपाल में आयोजित होने वाले 'नेपाल-भारत न्यायिक संवाद' कार्यक्रम में भाग लेने के लिए नेपाल यात्रा पर हैं।

ट्रंप कहें या नहीं, पीएम मोदी एक महान नेता हैं: सीएम देवेंद्र फडणवीस

मुंबई

भारत और अमेरिका में जारी टैरिफ विवाद के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने नरमी दिखाते हुए पीएम मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताया। इस बात पर अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ट्रंप कहें या नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक महान नेता हैं। इस दौरान उन्होंने यह भी साफ किया कि भारत अपनी विदेश नीति खुद तय करता है और किसी देश के दबाव में नहीं आता। बता दें कि फडणवीस का ये बयान तब आया जब हाल ही में अपने एक बयान में ट्रंप ने कहा था कि मैं हमेशा नरेंद्र मोदी का दोस्त रहूंगा, वह एक महान प्रधानमंत्री हैं।

लेकिन इस वक्त जो वो कर रहे हैं, वह मुझे पसंद नहीं है। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका ने भारतीय सामानों पर 50% तक टैरिफ (शुल्क) लगा दिया है और भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने पर 25% अतिरिक्त ड्यूटी लगा दी गई है। भारत सरकार ने इसे अनुचित, अन्यायपूर्ण और अकारण बताया है। सीएम फडणवीस ने कहा कि ट्रंप कुछ भी कहें, मोदी जी तो महान हैं ही। पूरी दुनिया के नेता उन्हें महान मानते हैं। उन्होंने कहा कि आज का भारत, मोदी जी का भारत है, जो अपनी विदेश नीति खुद तय करता है और किसी के दबाव में नहीं आता। उन्होंने आगे कहा कि भारत का 'विकसित भारत' बनने का सफर रुकने वाला नहीं है। फडणवीस ने यह बात अपने सरकारी आवास 'वर्षा' पर गणेश विसर्जन के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कही। इस दौरान उन्होंने लोगों से गणेश विसर्जन को पारंपरिक और शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की।

वापस आएगा नीरव मोदी और मेहुल चोकसी? ब्रिटेन की टीम ने किया तिहाड़ जेल का दौरा

ब्रिटेन की टीम ने तिहाड़ जेल का निरीक्षण किया, सुरक्षा इंतजामों को देखा, भारत सरकार ने भरोसा दिलाया कि प्रत्यर्पित आरोपियों को सुरक्षित माहौल मिलेगा

नई दिल्ली

भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि देश से भागे हुए बड़े आर्थिक अपराधी और आरोपी वापस लाए जा सकें। इन्हीं प्रयासों के तहत ब्रिटेन की क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस की एक टीम ने हाल ही में दिल्ली की तिहाड़ जेल का निरीक्षण किया। इसका मकसद था यह देखना कि भारत में लाए जाने वाले भगोड़े अपराधियों को सुरक्षित माहौल मिलेगा या नहीं। सूत्रों के मुताबिक, सीपीएस की टीम ने तिहाड़ जेल के हाई-सिक्योरिटी वार्ड का दौरा किया वहां मौजूद कैदियों से बातचीत। भारतीय अधिकारियों ने ब्रिटिश टीम को भरोसा दिलाया कि यदि जरूरत हुई तो जेल परिसर में खास एनक्लेव बनाई जाएगी, जहां हाई-प्रोफाइल आरोपी सुरक्षित रह सकें।

भारत सरकार ने दिया आश्वासन

भारत सरकार ने ब्रिटेन को यह भी आश्वासन दिया है कि किसी भी आरोपी से जेल में गैरकानूनी पूछताछ नहीं होगी। दरअसल, पहले कई बार ब्रिटिश अदालतों ने भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध को इसलिए खारिज किया था क्योंकि उन्हें भारतीय जेलों की स्थिति पर आपत्ति थी।

इंडिगो की फ्लाइट खराबी के कारण बीच रास्ते से ही लौटी

नई दिल्ली

संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी जाने वाली इंडिगो की एक उड़ान को तकनीकी खराबी के कारण शुक्रवार देर रात केरल के कोच्चि स्थित कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर वापस लौटना पड़ा। विमान में सवार सभी 180 यात्री सुरक्षित हैं, जिन्हें दूसरे विमान से अबू धाबी ले जाया गया। हवाई अड्डे के प्रवक्ता ने बताया कि अबू धाबी जा रही इंडिगो एयरलाइंस की एक उड़ान संख्या 6ई-1403 (सीओके-एयूएच) को देर रात तकनीकी खराबी के कारण कोच्चि वापस लौटना पड़ा।

राजस्थान में बारिश से हाहाकार, बीसलपुर बांध के 2 और गेट खोले

अजमेर

अजमेर, जयपुर और टोंक जिले के करीब एक करोड़ लोगों की प्यास बुझाने वाले बीसलपुर बांध के दो और गेट खोल दिए गए हैं। आज यानी 6 सितंबर को प्रति सेकंड 1 लाख 20 हजार क्यूसेक की रफ्तार से पानी की निकासी जा रही है। अब तक बांध के 8 चैनल गेट खोले जा चुके हैं। बीसलपुर बांध के चार गेट दो मीटर और अन्य चार गेट तीन मीटर तक खोले गए, जिनसे पानी की निकासी हो रही है। लगातार बारिश के काण बांध में अधिक पानी भर गया है। इस बांध में कुल 18 गेट हैं, जिनमें से 8 गेट खोल दिए गए हैं।

24 जुलाई को हुई था ओवरफ्लो

बांध के पानी पर निगरानी रखने वाले जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता मनीष बंसल ने बताया कि इस वर्ष बीसलपुर बांध बीते 24 जुलाई को ही ओवरफ्लो हो गया था, तभी से बांध से पानी की निकासी हो रही है। पिछले 43 दिनों से बांध में पानी तेजी से भर रहा है।

बनास नदी पर बना है बांध

प्रशासन इस बार ईसरदा बांध में भी पानी जमा कर रहा है, इसलिए बीसलपुर बांध के पानी पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। ईसरदा और बीसलपुर बांध के बीच 90 किलोमीटर की दूरी है। दोनों बांध बनास नदी पर बने हुए हैं।

कितना पानी निकला?

जानकार सूत्रों के अनुसार पिछले 43 दिनों में जितना पानी बीसलपुर से निकाला गया है, उससे अगले दो साल तक जयपुर, अजमेर और टोंक जिले में पेयजल की सप्लाई की जा सकती थी। इन तीनों जिलों में प्रतिदिन एक हजार एमएलडी पानी की सप्लाई होती है। इस समय बांध के 8 गेट खोल कर पानी की निकासी हो रही है, इसलिए बांध का विहंगम दृश्य देखने को मिल रहा है।

8 गेट खोले जा चुके

गौरतलब है कि शुक्रवार को कैचमेंट एरिया में हो रही बारिश से बीसलपुर बांध में पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। इसे देखते हुए बांध के 6 गेट खोलकर अतिरिक्त पानी की निकासी की जा रही थी। गुरुवार को महज डेढ़ घंटे बाद पानी की आवक तेज होने पर दो गेटों को दो-दो मीटर तथा चार गेटों को एक-एक मीटर खोलकर कुल 48,080 क्यूसेक पानी की निकासी की गई थी। शनिवार को दो गेट और खोले गए हैं।

'मां के बयान के बावजूद बच्चे का डीएनए परीक्षण उसके मातृत्व का अपमान'

नई दिल्ली

ओडिशा हाई कोर्ट की एकल पीठ के न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.पी. राउत्रे ने यह टिप्पणी करते हुए निचली अदालत का फैसला बरकरार रखा। गौरतलब है कि संपत्ति बंटवारे के एक मामले में विरोधी पक्ष के 58 साल के व्यक्ति के पिता का पता लगाने के लिए उसका डीएनए परीक्षण का निर्देश देने की मांग की गई थी। जिसे निचली अदालत ने खारिज कर दिया था। जिसके बाद निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा। वहीं अब हाईकोर्ट ने भी निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति राउत्रे ने एक सितंबर को अपने फैसले में कहा कि मैं इस मामले में व्यक्ति का डीएनए परीक्षण कराने के लिए इसे उपयुक्त मामला नहीं मानता। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता की अपील को अस्वीकार करने वाली निचली अदालत के आदेश में मुझे कोई कमी नहीं दिखती।

साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि संबंधित व्यक्ति अब 58 वर्ष का है और इस उम्र में डीएनए टेस्ट कराने से कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आएगा। गवाही में व्यक्ति की मां ने साफ कहा है कि वह उसके पति ठूटा बुडुला से उत्पन्न संतान है। और विपक्षी पक्ष न तो मां की वैध शादी पर सवाल उठा पाया और न ही उसकी पत्नी होने की स्थिति पर। इसलिए किसी तीसरे पक्ष को पितृत्व पर प्रश्न उठाने का अधिकार नहीं है।

कैमिकल फैक्ट्री की आड़ में ड्रग्स का कारोबार, 12000 करोड़ का ड्रग बरामद

हैदराबाद

मुंबई पुलिस ने तेलंगाना एक बड़े ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया है। ठाणे की मीरा रोड स्थित पुलिस ने भारी मात्रा में एमडी (मेफेड्रोन) बरामद की है, जिसकी कुल कीमत 12,000 करोड़ रुपये आंकी गई है। अधिकारियों के अनुसार, तेलंगाना की एक फैक्ट्री पर ड्रग्स बनाए जाते थे।

जब पुलिस ने उस जगह पर छापेमारी की, तो ड्रग्स बनाने वाला 35,000 लीटर कैमिकल भी बरामद किया गया। जांच में पता चला है कि इस फैक्ट्री में पिछले कई सालों से ड्रग्स बनाया जा रहा था।

मुंबई भेजे जाते थे ड्रग्स

यह ड्रग्स फैक्ट्री में तैयार किए जाते थे और फिर स्थानीय आरोपियों और एजेंट्स के द्वारा यह ड्रग्स मुंबई भेजे जाते थे। कैमिकल फैक्ट्री के नामपर इस जगह बड़े पैमाने पर ड्रग्स का कारोबार हो रहा था।

अनअकैडमी सेंटर संचालक 7 करोड़ रुपये फीस लेकर फरार, 500 से अधिक छात्र परेशान

अनअकैडमी सेंटर संचालक फरार

छात्रों से सात करोड़ रुपये की फीस लेकर भागा

सेंटर पर पहुंची पुलिस की टीम

आगरा

भगवान टॉकीज स्थित अनअकैडमी सेंटर (जो नीट, जेईई और फाउंडेशन बैच की तैयारी कराता था) का प्रबंधन 500 से अधिक छात्रों की सात करोड़ से अधिक की फीस लेकर फरार हो गया। जेईई ड्रापर छात्र प्रांजल और जैनव यादव समेत कई छात्र परेशान हैं। आंचल का यह आखिरी प्रयास है, उसने 60,000 रुपये दिए। तीन दिन से डीएम के आदेश बताकर कर रखी थी छुट्टी

सेंटर प्रबंधन ने तीन दिन से डीएम के आदेश बताकर स्टूडेंट्स की छुट्टी कर रखी थी। शनिवार को काउंसलर पुनीत ने छात्रों से कहा कि सेंटर दूसरी कोचिंग में मर्ज हो रहा है। जिसके बाद छात्रों ने स्वजन के साथ फीस वापस करने की बात कही तो हंगामा शुरू हो गया।

अरुणाचल प्रदेश में ग्लेशियर पिघलने से सैलाब का खतरा, हिमाचल समेत इन राज्यों में भी बढ़ रहा झीलों का आकार

ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिसके कारण राज्य पर खतरा मंडरा रहा है। ग्लेशियर पिघलने से झीलों में ज्यादा पानी जमा हो रहा है। ऐसे में झील फटने या बाढ़ आने से कई इलाकों में भारी तबाही मच सकती है। हाल ही एक रिपोर्ट के अनुसार, पूर्वी हिमालय में स्थित कुछ ग्लेशियर 1.5 मीटर की तेजी से पिघल रहे हैं। सेंटर फॉर अर्थ साइंस एंड हिमालय स्टडीज ने यह खुलासा किया है।

अरुणाचल में पिघल रहा ग्लेशियर

पिछले कुछ समय से तवांग के गोरीचेन पर्वत में स्थित खांगरी ग्लेशियर पर नजर रखे हुए हैं। एक सैटेलाइट सर्वे के दौरान इस इलाके से चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। 2016 से 2025 के बीच यहां मौजूद झीलों का आकार तेजी से बढ़ा है। ऐसे में अगर झीलें फटीं तो अरुणाचल के कई हिस्सों में फ्लैश फ्लड्स आ सकते हैं।

छात्रों के साथ मारपीट भी की

जितेंद्र, गौरव, सुमित महाजन, सिद्धार्थ मेहता ने अप्रैल 2025 में पार्टनरशिप में कोचिंग खोली थी। शिक्षकों की सैलरी नहीं दी गई, फिजिक्स शिक्षक ऋषभ ने छात्रों के साथ मारपीट भी की।

राजा रघुवंशी मर्डर केस में 790 पन्नों की चार्जशीट दाखिल, अदालत के सामने आई सोनम और उसके प्रेमी की करतूत

शिलांग

26 मई 2025 को मेघालय में हनीमून मनाने गया इंदौर का एक कपल अचानक लापता हो गया। 2 जून 2025 को पति की लाश मेघालय के जंगलों से बरामद हुई और 8 जून 2025 को पत्नी गाजीपुर में पकड़ी गई। राजा रघुवंशी मर्डर केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। राजा की हत्या की साजिश उसी की पत्नी सोनम रघुवंशी ने रची थी। वहीं, अब मेघालय पुलिस ने 790 पन्नों की चार्जशीट अदालत में पेश की है।

सोनम समेत 5 पर आरोप

मेघालय पुलिस की इस चार्जशीट में सोनम को आरोपी बताया गया है। राजा की हत्या में सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा समेत उसके 3 दोस्तों विशाल सिंह चौहान, आशीष सिंह राजपूत और आनंद कुमार शामिल थे। मेघालय पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) 238 ए/ 61(2) के तहत मामला दर्ज किया था। चार्जशीट के अनुसार, "21 मई 2025 को राजा और सोनम मध्य प्रदेश से शिलांग पहुंचे। वो सोहरा गए और 26 मई 2025 को लापता हो गए। दोनों की तलाश में फौरन सर्च ऑपरेशन चलाया गया। 2 जून 2025 को राजा की लाश गहरी खाई से बरामद की गई।"

अब यमुना खादर, चिल्ला, पुराना उस्मानपुर, गढ़ी मांडू और सोनिया विहार के किसान यमुना का जलस्तर कम होने का इंतजार कर रहे

बारिश...बाढ़ और बर्बादी: 'यमुना ये तूने क्या किया..'

n किसानों को खासा नुकसान उठाना पड़ा है। किसान सवाल पूछ रहे हैं कि यमुना तूने ये क्या किया

नई दिल्ली

उफान पर आई यमुना ने न केवल लोगों को बेघर किया, बल्कि किसानों की सारी फसलें भी बर्बाद कर दी है। इससे किसानों को खासा नुकसान उठाना पड़ा है। किसान सवाल पूछ रहे हैं कि यमुना तूने ये क्या किया। ऐसे में अब यमुना खादर, चिल्ला, पुराना उस्मानपुर, गढ़ी मांडू और सोनिया विहार के किसान यमुना का जलस्तर कम होने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि वह फिर से खेतों में लौट सके और नई फसलें बो सके। यमुना डूब क्षेत्र में किसान अधिकतर सब्जी की फसलें उगा रखे थे। इनमें बैंगन, भिंडी, लौकी, मूली, गाजर, टमाटर, गोभी, मटर, आलू, प्याज और मिर्च समेत अन्य फसलें शामिल थीं।

लोन और उधार लेकर उगाते हैं फसल

किसानों ने बताया कि वह फसलें उगाने के लिए जमीन को पट्टे पर लेते हैं। इसके लिए वह अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और बैंकों से लोन लेते हैं। दिन-रात मेहनत कर फसल उगाते हैं। उनका कहना है कि उगाई हुई फसलों में से कुछ हिस्सा वह अपनी जरूरतों के मुताबिक रख लेते हैं, बाकी कि फसलें वह पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेस-1, मयूर विहार फेस-2, पांडव नगर, त्रिलोकपुरी, लक्ष्मी नगर, शकरपुर, गाजीपुर अनाज मंडी व अन्य इलाको में बेच देते हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे ही उनका घर परिवार चलता है।

फसल बेचकर जो पैसे आते हैं, उसी से ब्याज और उधार के पैसे देते हैं लेकिन बाढ़ ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। उन्हें सड़क पर लाने के साथ-साथ कर्जदार भी बना दिया है।

सुरक्षा के नहीं हैं ठीक इंतजाम

यमुना खादर की महिला किसानों का आरोप है कि सरकार की ओर से जो टेंट लगाए गए हैं, उनमें सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं हैं। रात के समय बाहरी व्यक्ति यहां आकर शराब का सेवन करते हैं और शराब की बोतलों को सड़क पर फेंक देते हैं। नशे की हालत में कुछ लोग शिविरों के अंदर ताका-झांकी करते हैं। ऐसे में उन्हें डर लगा रहता है कि कुछ अनहोनी न हो जाए।

लोगों से बातचीत

इस बार मैंने मक्के की खेती की थी। इसके लिए किराये पर खेत लिया था। उसमें अच्छी फसलें भी उग आई थी, लेकिन बाढ़ से सब फसलें बर्बाद हो गईं। साथ ही, अब सर पर कर्ज भी हो गया है।

- आशा राम, किसान।

सामान यमुना में डूब चुका है। कई महीनों तक दिन-रात मेहनत करते हुए फसल उगाई थी, वह भी बर्बाद हो गई हैं। अब खेतों का पानी कम होगा, तो फिर से फसल उगाऊंगी।

- राम स्नेह, किसान।

रात के समय कुछ बाहरी लोग यहां पर आकर शराब का सेवन करते हैं। उसके बाद शराब की बोतलें पुल के नीचे फेंक देते हैं। कुछ लोग शराब के नशे में इधर-उधर घूमते रहते हैं।

- प्रेम मति, किसान।

बाढ़ पीड़ितों की हर जरूरत का ध्यान रख रहे : सीएम रेखा गुप्ता

बाढ़ पीड़ितों को सरकार, जनप्रतिनिधि व एनजीओ मदद करने में जुटे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार बाढ़ पीड़ितों की हर जरूरत का ध्यान रख रही है। राहत शिविरों में भोजन, पानी, दवाइयां और शौचालय की व्यवस्था है। किसानों के मवेशियों के लिए चारा भी मुहैया कराया जा रहा है। बाढ़ पीड़ितों की सुरक्षा व सुविधा में कोई कमी नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि स्थिति नियंत्रण में है। यमुना का जलस्तर अब कम हो रहा है। सरकार 24 घंटे हालात पर नजर रख रही है। सभी जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) प्रभावित इलाकों में मौके पर हैं जो पीड़ितों को राहत पहुंचाने में जुटे हैं। वहीं, मुख्यमंत्री ने कैंप कार्यालय मुख्यमंत्री जनसेवा सदन से डिविजनल कमिश्नर और सभी डीएम के साथ ऑनलाइन बैठक की जिसमें राहत कार्यों की समीक्षा की गई और स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।

कोरोना में जान गंवाने वाले शिक्षक के परिवार को मिलेगा मुआवजा

नई दिल्ली

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को निठारी स्थित दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) स्कूल के पूर्व प्रिंसिपल शिवनाथ प्रसाद के परिवार को एक करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया है, जिन्होंने कोरोना महामारी के दौरान ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवा दी थी। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि अदालत को इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अपीलकर्ता के दिवंगत पति की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु कोरोना महामारी के दौरान ड्यूटी करते समय कोरोना से संक्रमित होने के कारण हुई। अदालत ने निठारी स्थित एमसीडी प्राइमरी बॉयज स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा 24 अप्रैल, 2023 को जारी एक पत्र की जांच की, जिसमें संकेत दिया गया था कि पूर्व प्रिंसिपल कोरोना महामारी के दौरान ड्यूटी पर तैनात थे। उन्होंने कोरोना के टीके लगवाने से संबंधित कार्य किया था। अदालत ने मृतक की पत्नी द्वारा एकल पीठ के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका स्वीकार कर ली। याचिका में कहा गया है कि शिवनाथ प्रसाद मई 1993 में दिल्ली सरकार में सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए थे और अपनी मृत्यु के समय वे एमसीडी प्राइमरी बॉयज स्कूल, निठारी के प्रधानाचार्य थे। याचिका में कहा गया है कि मई 2020 में दिल्ली सरकार की ओर से घोषणा की गई थी कि कोरोना महामारी के दौरान ड्यूटी के दौरान कोरोना महामारी से संक्रमित होने से मरने वाले कर्मचारी-अधिकारी के परिवार को 1 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी।

लाल किला परिसर से कीमती कलश चोरी, जांच जारी

नई दिल्ली

दिल्ली के लाल किले परिसर से कीमती कलश चोरी हुआ है मामले को लेकर दिल्ली पुलिस का बयान सामने आया है। सीसीटीवी के जरिए आरोपी की पहचान कर ली गई है। पुलिस ने बताया कि लाल किला परिसर में आयोजित एक धार्मिक अनुष्ठान के दौरान लाल किला परिसर से एक बड़ी झारी, सोना, नारियल और लगभग 760 ग्राम सोना, हीरे, माणिक और पन्ना जड़ी एक छोटी झारी चोरी हो गई।

पुलिस ने आगे कहा कि व्यवसायी सुधीर जैन प्रतिदिन पूजा के लिए कलश लाते थे। पिछले मंगलवार को यह कार्यक्रम के बीच में मंच से गायब हो गया। संदिग्ध की गतिविधियां सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई हैं।

बाढ़: दिल्ली पर खतरा बरकरार !... कुछ इलाकों में पानी घटा

नई दिल्ली

दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर कम हो रहा है, लेकिन खतरे के निशान से ऊपर है। जिससे राजधानी में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। शनिवार को यमुना नदी का जलस्तर 206.47 मीटर पर आ गया। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर मयूर विहार, यमुना बाजार, कश्मीरी गेट, और निगमबोध घाट जैसे क्षेत्रों में दिख रहा है। पुराने रेलवे ब्रिज पर यमुना का जलस्तर बीती पांच सितंबर को सुबह 7 बजे 207.33 मीटर दर्ज किया गया था, जो खतरे के निशान से काफी ऊपर था। हालांकि, जलस्तर में थोड़ी कमी देखी गई और जो 8 बजे तक 207.31 मीटर पर आ गया। अधिकारियों का कहना है कि जलस्तर दिन के दौरान और कम हो सकता है।

n राहत शिविरों में बच्चों के लिए अस्थायी स्कूल भी खोले गए हैं, ताकि बच्चों की पढ़ाई का सिलसिला न रुके

यमुना में जलस्तर हुआ कम, खतरा बरकरार

यमुना के जलस्तर में शुक्रवार को

0.43 मीटर की गिरावट दर्ज की गई, जिससे डूब क्षेत्र का पानी कम होने लगा है। हालांकि शाम 6 बजे पुराने रेलवे पुल पर जलस्तर अब भी खतरे के निशान (205.33 मीटर) से करीब 2 मीटर ऊपर रहा, जिसके चलते पुल से रेल संचालन बंद है। 27 ट्रेनें रद्द करनी पड़ीं और 18 को डायवर्ट किया गया।

बर्बाद हो गई फसलें

यमुना में उफान आने से न केवल लोग बेघर हुए हैं बल्कि किसानों की सारी फसलें भी बर्बाद हो गई हैं। इससे किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे में यमुना खादर, चिल्ला, पुराना उस्मानपुर, गढ़ी मांडू और सोनिया विहार के किसान यमुना का जलस्तर कम होने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि वह फिर से खेतों में लौट सके और नई फसलें लगा सके। यमुना डूब क्षेत्र में किसान अधिकतर सब्जी की फसलें उगा रखे थे। इनमें बैंगन, भिंडी, लौकी, मूली, गाजर, टमाटर, गोभी, मटर, आलू, प्याज और मिर्च समेत अन्य फसलें शामिल थीं।

मयूर विहार बना टेंट सिटी

दिल्ली के मयूर विहार पल्ला क्षेत्र में आई बाढ़ के बाद फ्लाईओवर के नीचे सैकड़ों लोगों ने प्रशासन की ओर से लगाए गए टेंटों में बसेरा बना लिया है। सड़क किनारे तने इन टेंटों के बीच जिंदगी ने जैसे मजबूरी में ही सही मगर एक नया रंग पकड़ लिया है। राहत शिविरों में बच्चों के लिए अस्थायी स्कूल भी खोले गए हैं, ताकि बाढ़ के बावजूद भी बच्चों की पढ़ाई का सिलसिला न रुक सके। साथ ही हेल्थ क्लीनिक भी बनाए गए हैं, जहां डॉक्टर लगातार बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं की जांच कर दवाई दी जा रही है।

बाईपास रोड परियोजना अधर में लटकी, खिड़की निवासी परेशान

n 15 सालों से अटका बाईपास लिंक रोड का काम
n खिड़की गांव के लोग जाम से परेशान

नई दिल्ली

प्रेस एन्क्लेव से स्वामी नगर तक बाईपास लिंक रोड का काम पिछले 15 सालों से अटका पड़ा है। इसका खामियाजा खिड़की गांव और खिड़की एक्सटेंशन में रहने वाले हजारों निवासियों को भुगतना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी हर दिन जाम और प्रदूषण की समस्या से जूझ रहे हैं। न तो वे इलाके की मुख्य सड़क से गुजरने वाली मुख्य सड़क पर अपने वाहन पार्क कर सकते हैं और न ही उनके बच्चे घर के बाहर खेल पा रहे हैं। जबकि पीड़ित निवासियों ने जनप्रतिनिधियों से लेकर संबंधित अधिकारियों तक कई बार बाईपास निर्माण की मांग की है, लेकिन आज तक उनकी समस्या को नजरअंदाज किया जा रहा है। बीआरटी के निर्माण के बाद वर्ष 2009 में जन कल्याण मोर्चा के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने प्रेस एन्क्लेव से स्वामी नगर तक चिराग दिल्ली नाले के साथ बाईपास रोड के निर्माण की मांग की थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने इस परियोजना पर सहमति जताते हुए इसे मंजूरी दे दी थी।

आरोपित को बार-बार रिमांड पर लेने पर पत्नी ने दी याचिका

n हाई कोर्ट ने पुलिस से स्थिति रिपोर्ट मांगी
n हाईकोर्ट ने रिमांड की वैधता पर उठाए सवाल

नई दिल्ली

अलग-अलग मामले में आरोपित सलीम अहमद उर्फ पिस्टल का बार-बार पुलिस रिमांड लेने के खिलाफ उसकी पत्नी द्वारा दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से स्थिति रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति गिरीश कथपालिया की पीठ ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह के अंदर स्थिति रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। मामले पर अगली सुनवाई पांच दिसंबर को होगी। अधिवक्ता कासिफ अतहर व अक्षय लोधी के माध्यम से याचिका दायर कर सलीम अहमद उर्फ पिस्टल की पत्नी ने कई प्राथमिकी में लगातार पुलिस रिमांड की वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। अधिवक्ता कासिफ अतहर ने तर्क दिया कि उनकी पति की पुलिस द्वारा एक मामले में रिमांड समाप्त होने पर पुलिस द्वारा दूसरी प्राथमिकी पर रिमांड लिया जा रहा है। यह भी तर्क दिया गया कि एक आरोपित को अलग-अलग एफआईआर में रिमांड पर लेना संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। यह भी कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को प्राथमिकी के रोटेशन के जरिए अनिश्चितकालीन कस्टडी में नहीं रखा जा सकता। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और उचित प्रक्रिया के अधिकार को सर्वोपरि रहना चाहिए। वहीं, दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त स्थायी अधिवक्ता अमोल सिन्हा ने पीठ को बताया कि सलीम अहमद उर्फ पिस्टल पर 14 प्राथमिकी हैं और गिरफ्तारी के दौरउ उसके पास से 26 पिस्टल व 800 कारतूस

टीवी एक्टर आशीष कपूर का एम्स में हुआ पोटेंसी टेस्ट

नई दिल्ली। टीवी अभिनेता आशीष कपूर का एम्स में एक मेडिकल पोटेंसी टेस्ट कराया गया है। यह जांच रिपोर्ट कथित रेप मामले में महत्वपूर्ण सबूत के रूप में काम करेगी, जिसमें उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने कहा कि टीवी अभिनेता आशीष कपूर का एम्स में एक मेडिकल पोटेंसी टेस्ट एम्स में कराया गया है। अधिकारियों ने बताया कि यह रिपोर्ट कथित रेप मामले में महत्वपूर्ण सबूत के रूप में काम करेगी, जिसमें उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है।

मथुरा रोड पर दो मंजिला बिल्डिंग ढही

नई दिल्ली

मथुरा रोड पर बदरपुर थाने के पास इंदिरा नर्सरी की बगल की दो मंजिला बिल्डिंग शनिवार को धराशाई हो गई। सूचना मिलते ही दमकल की तीन गाड़ियां व पुलिस मौके पर पहुंची। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। व्यावसायिक गतिविधियों के लिए बनाई गई बिल्डिंग पिछले काफी समय से बंद थी। इसके पास ढाबा भी बंद था। पुलिस ने कुछ देर के लिए मार्ग को बंदकर राहत कार्य चालू कराया।

अनधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्यों को मिलेगी गति

नई दिल्ली

अनधिकृत कॉलोनियों में नागरिक सुविधाएं मुहैया कराने के काम में अब तेजी लाई जाएगी। इसी सिलसिले में इन कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिए एक साथ 39 टेंडर जारी किए गए हैं। इनके तहत इन कॉलोनियों में सड़कें, गलियां, नालियां और सीवर बनाने का काम किया जाना है। दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि काम के साथ-साथ गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। भाजपा सत्ता में वापसी के लिए अनधिकृत कॉलोनियों के लोगों के योगदान को भी अहम मान रही है। इन कॉलोनियों में मुस्तफाबाद, करावल नगर, शिव विहार, गांधी नगर, बादली समेत कई अन्य कॉलोनियां शामिल हैं।

1984 सिख विरोधी दंगा: सज्जन कुमार याचिका मंजूर

नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार की याचिका को मंजूरी दे दी, जिसमें उन्होंने दो मीडिया हाउस से 2 नवंबर से 11 नवंबर 1984 के बीच प्रकाशित कुछ समाचार रिपोर्टों की प्रमाणित प्रतियां रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश मांगा था। सज्जन कुमार जनकपुरी और विकासपुरी पुलिस स्टेशनों में दर्ज सिख विरोधी दंगा मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं।

यमुना विहार इलाके में बन रही हैं छह बैक लेन, मिलेगी राहत

n यमुना विहार स्थित सी-4 ब्लॉक की डीडीए मार्केट में शिलान्यास समारोह का आयोजन किया गया

नई दिल्ली

यमुना विहार स्थित सी-4 ब्लॉक की डीडीए मार्केट में शिलान्यास समारोह का आयोजन किया गया। इसमें घोंडा विधायक अजय महावर ने सी-4 ब्लॉक की तीन, सी-7 ब्लॉक की एक और सी-8 ब्लॉक की दो बैक लेन का शिलान्यास किया। महावर ने बताया कि लंबे समय से क्षेत्रवासी बैक लेन निर्माण की मांग कर रहे थे। उनकी मांग को प्राथमिकता देते हुए यह कार्य शुरू कर दिया गया है। 17.86 लाख रुपये की लागत से निर्माण कार्य होगा। यह कार्य तीन से चार महीने में पूरा हो जाएगा। इसके बाद लोगों को काफी सुविधा महसूस होगी।

इसके साथ ही क्षेत्र की अन्य गलियों और बुनियादी ढांचे का विकास प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। जनता की भागीदारी और सहयोग से विकास कार्यों को गति मिलेगी।

इस दौरान जिला अध्यक्ष डॉ. यूके चौधरी, मंडल अध्यक्ष विपिन कुमार, मुकेश गोयल, हरीश शर्मा, जितेंद्र भदौरिया, विजय चौधरी, दीपक जैन, न्याति जैन, मनोज परिहार, अजीतपाल सिंह, मनोज शर्मा, विद्याराम यादव सहित आरडब्ल्यूए सदस्य मौजूद रहे।

यमुना का जलस्तर थोड़ा बढ़ने पर क्यों डूब जाती है दिल्ली?

नई दिल्ली

यमुना की सफाई के बड़े-बड़े दावे इसकी गहराई में ही अटके हुए हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि छह दशक में यमुना की जल धारण क्षमता 50 फीसदी कम हो गई है। यानी नदी की गहराई अपनी मूल गहराई से आधी रह गई है। गहराई में इस कमी का सबसे बड़ा कारण इसमें जमा गाद है। इसकी सफाई के नाम पर सरकार ने हर बार बजट और टेंडर जारी किए, लेकिन इसकी सफाई नहीं हुई। अगर यह गाद हटा दी गई होती तो हथिनी कुंड से छोड़ा गया 3.29 लाख क्यूसेक पानी नदी खुद ही सोख लेती। यह दिल्ली की सड़कों

या घरों की चौखट पर इस तरह न भटकता। लोगों के लिए संकट न खड़ा होता। सितंबर 1978 में हथिनी कुंड से आठ लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, तब दिल्ली में लोहा पुल के पास यमुना का जलस्तर 207.49 मीटर तक पहुंच गया था। वहीं, जुलाई 2023 में मात्र 3.59 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से जलस्तर 208.66 मीटर और इस वर्ष 3.29 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से जलस्तर 204.88 मीटर पर पहुंच गया। इससे साफ है कि 1978 के मुकाबले यमुना की जलधारण क्षमता करीब 50 फीसदी कम हो गई है। इसका मुख्य कारण

n नदी के बाढ़ क्षेत्र में अतिक्रमण व निर्माण और उसकी तलहटी में गाद जमा होना है

नदी के बाढ़ क्षेत्र में अतिक्रमण व निर्माण और उसकी तलहटी में गाद जमा होना है। दिल्ली व केंद्र सरकार द्वारा गठित कमेटियों की रिपोर्ट में भी इसे लेकर चिंता जताई जा चुकी है। इसके बाद भी समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। अब भी यमुना खादर में निर्माण कार्य के साथ ही मलबा डाला जा रहा है। केंद्रीय जल आयोग के अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली से करीब 180 किलोमीटर दूर हरियाणा के यमुनानगर स्थित हथिनी कुंड बैराज से छोड़ा गया पानी अब पहले की तुलना में कम समय में दिल्ली पहुंचता है। इसका मुख्य कारण नदी क्षेत्र में अतिक्रमण और गाद है। पहले नदी का पानी अधिक चौड़े क्षेत्र से गुजरता था, जिससे उसकी गति धीमी थी। अब प्रवाह क्षेत्र की चौड़ाई कम है, इसलिए गति बढ़ गई है। वहीं, नदी से गाद न हटाने के कारण सिग्नेचर ब्रिज, आईटीओ बैराज, यमुना बैंक समेत कई जगहों पर रेत के टीले बन गए हैं, जो नदी के प्रवाह में बाधा बन रहे हैं।

दिल्ली को साफ-सुथरा बनाने की पहल पर काम कर रही सरकार

n सांसद ने सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया
n निगम के प्रयासों को सराहा

नई दिल्ली

भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा है कि दिल्ली को स्वच्छ बनाने के लिए जनता के सहयोग के साथ-साथ सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना और उन्हें हर तरह के संसाधन उपलब्ध कराना भी जरूरी है। वे पीवीआर साकेत में "दिल्ली को कचरे से मुक्ति" विषय पर आयोजित "राहगीरी" कार्यक्रम में बोल रहे थे। दक्षिणी दिल्ली के सांसद बिधूड़ी ने कहा कि आज दिल्ली की आबादी तीन करोड़ हो गई है, लेकिन जरूरत के हिसाब से सफाई कर्मचारियों की संख्या नहीं बढ़ाई गई है। दिल्ली में जलभराव पर उन्होंने कहा कि यमुना का जलस्तर बढ़ने से किनारे पानी से जरूर भर गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार और नगर निगम के उल्लेखनीय प्रयासों से पूरी दिल्ली साफ है। कार्यक्रम में महरौली विधायक गजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि दिल्ली के लोगों को स्वस्थ और जागरूक जीवनशैली अपनानी चाहिए।

संपादकीय

महंगी स्वास्थ्य सेवाएं

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने पिछले दिनों इंदौर में महंगी स्वास्थ्य एवं शिक्षा प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाले भारत में महंगी चिकित्सा सुविधाएं निःसन्देह चिंता का विषय है। हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि निजी अस्पताल मरीजों को एटीएम समझते हैं। असल में भारत का स्वास्थ्य क्षेत्र गंभीर विसंगतियों से भरा हुआ है। एक तरफ तो हम सस्ती दवाओं और वैक्सीन के उत्पादन में विश्व भर में शीर्ष पर है लेकिन हमारे ही नागरिक दुनिया में अपने स्वास्थ्य पर अपनी जेब से सर्वाधिक पैसा भी खर्च करते हैं। देश में आर्थिक भेदभाव कम हो रहा है इसे दुनिया के तमाम संगठन मान रहे हैं लेकिन यह भी तथ्य है कि देश में करीब 7 फीसदी लोग महंगे इलाज के कारण गरीबी के गर्त में हर साल पहुँच जाते हैं। पिछले साल दिल्ली के एक निजी अस्पताल का किडनी उपचार सम्बंधित बिल 2473894 रुपये का बनाया गया था। यह बानगी भर है कि निजी क्षेत्र का स्वास्थ्य तन्त्र किस तरह काम कर रहा है। एसीकेओ इंडिया हेल्थ इंडेक्स की हालिया रिपोर्ट कहती है कि देश में हर साल इलाज महंगा होने की दर 14 फीसदी है। एक सरकारी आंकड़े के मुताबिक आयुष्मान भारत जैसी बेहतरीन योजना के बाबजूद देश में अभी भी 40 फीसदी लोग अपने स्वास्थ्य पर अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं जिसे ओओपीई (आउट औफ पॉकेट एक्सपेंडिचर) कहा जाता है। यह आंकड़ा वैश्विक औसत 18 फीसदी से काफी अधिक है। हालांकि आयुष्मान भारत के बाद स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च 29 से बढ़कर 48 प्रतिशत हुआ है, यह एक अच्छा संकेतक है। डॉ मोहन भागवत ने जिस समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट किया है वह आम आदमी के दर्द को अधोरेखित करने वाला है क्योंकि 23 फीसदी लोग अभी भी अस्पताल के खर्चों के लिए उधार लेने पर मजबूर हैं।

महंगी स्वास्थ्य सेवाओं का सबसे अहम पहलू दवाओं से जुड़ा है क्योंकि दवाएं अभी भी बहुत महंगी है। निजी क्षेत्र में उपचार के दौरान 70 से लेकर 90 फीसदी तक एलोपैथी दवाएं ब्रांडेड ही उपयोग में आ रही हैं ,जबकि सरकार ने सस्ती जेनरिक दवाओं के लिए प्रधानमंत्री जन औषिधि केंद्र आरम्भ किये है। इन केंद्रों पर 90 फीसदी तक दवाओं के दाम ब्रांडेड दवाओं की तुलना में कम होते हैं। जेनेरिक दवाओं के लिए सरकारी प्रयास फार्मा लॉबी के दबाव में फलीभूत नहीं हो पा रहे हैं।अभी तक देश भर में 15057 जेनेरिक स्टोर खुल पाए हैं और विसंगति यह है कि इन स्टोरों में ब्रांडेड दवाओं की बिक्री भी जेनेरिक के साथ में की जा रही है। भारत में एलोपैथी दवाओं का सालाना कारोबार 4.2 लाख करोड़ का है। करीब 3 लाख करोड़ की खपत भारतीय बाजार में है और 1.2 लाख करोड़ की दवाएं निर्यात की जाती हैं।

सरकार को सर्वोपरि प्राथमिकता पर इसी क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है।

अभी जेनेरिक दवाओं की तुलना में ब्रांडेड दवाओं की कीमतें 30 से 2000 फीसदी तक महंगी बिक रही हैं। ब्रांडेड दवाओं के इस संगठित कारोबार को रोक कर महंगे इलाज को झटके में जमीन पर लाया जा सकता है।

असल में देश को हरित क्रांति की तरह दवा क्रांति की आवश्यकता भी है क्योंकि अभी इस क्षेत्र में कोई खास विनियमन नहीं है। आजादी के समय यूरोपीय पेटेंट वाली दवाएं इसलिए महंगी थी क्योंकि हमारे यहां उत्पादन ही नहीं था। 1970 में पेटेन्ट एक्ट के बाद भारत ने दवाओं के निर्माण में अभूतपूर्व काम किया। आज हम विश्व के अग्रणी उत्पादक हैं। कोरोना वैक्सीन में भारत का यह दम दुनिया ने देखा ही है।

महंगे इलाज का दूसरा कारक स्वास्थ्य क्षेत्र के कॉपोरेटाइजेशन (निगमीकरण) का है क्योंकि देश में 1980 तक स्वास्थ्य प्रदाता के रूप में धर्मार्थ न्यास या फाउंडेशन ही सक्रिय थे और सबका उद्देश्य मुनाफा नहीं सेवा मुख्य था। इसके बदले में सरकार ने गरीबों को सस्ते इलाज और स्थानीय रोजगार के नाम पर मुफ्त जमीनें दी और टैक्स रियायतें उपलब्ध कराई। आज इस क्षेत्र में नए खिलाड़ी आ गए हैं जिनका उद्देश्य कारपोरेट घरानों की तरह कारोबार करना है।

यही कारण है कि देश के दो तिहाई अस्पताल शहरी क्षेत्रों में हैं और इन अस्पतालों से महज एक तिहाई आबादी को ही सेवाओं का कवरेज मिल रहा है।

निजी अस्पतालों की सघनता शहरी क्षेत्रों में घनीभूत है क्योंकि निवेशकों की नजर ज्यादा पैसे वाले क्षेत्रों में ही होती हैं। ध्यान देने वाला तथ्य यह है कि इन शहरी क्षेत्रों में आने वाले अधिसंख्य मरीज उन बीमारियों के होते हैं जिनको आरम्भिक शिकायत पर ही ठीक किया जा सकता है लेकिन सार्वजनिक सेवाओं का ढांचा

भारत एआई क्रांति में अग्रणी बन दुनिया का नेतृत्व करें

पेरिस में हुए दो दिवसीय एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) एक्शन समिट ने जहां दुनिया के लिए आर्टिफिशल इंटेलिजेंस के महत्व को उजागर किया, वहीं यह भी साफ कर दिया कि इस मामले में होड़ के बावजूद सभी देशों का आपसी तालमेल बनाए रखते हुए सावधानी से आगे बढ़ना जरूरी है। एआई से बदलती दुनिया के चमत्कार वरदान से कम नहीं है, लेकिन इससे जुड़ी चुनौतियां एवं खतरे इसे अभिशाप में भी बदल सकते हैं। बहुत आवश्यक है कि इसके उपयोग के संदर्भ में कोई वैश्विक ढांचा एवं नियंत्रण का केन्द्र एवं नीति बने। क्योंकि एआई के दुरुपयोग के खतरे किसी से छिपे नहीं। अभी एआई का उपयोग अपने प्रारंभिक चरण में ही है, लेकिन उससे पैदा होने वाली कई चुनौतियां एवं खतरों ने सिर उठा लिया है। लेकिन इस नई तकनीक से जीवनशैली, शिक्षा, चिकित्सा, युद्ध, सेना, शासन-प्रशासन, चुनाव, व्यापार, विचार आदि में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। भारत एआई को लेकर बहुत उत्साहित है और दुनिया में एआई का सबसे बड़ा केन्द्र बनने को भी तैयार है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ इस शिखर बैठक की सह-अध्यक्षता की बल्कि अगली शिखर बैठक की मेजबानी करने की पेशकश भी करते हुए बता दिया कि भारत इस पहल को कितनी गंभीरता से लेता है।

भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर होते हुए तकनीकी विकास की दृष्टि से भी सफलता के नये झंडे गाड रहा है। एआई को लेकर भारत की सोच सकारात्मक एवं विकासमूलक है इसीलिये प्रधानमंत्री मोदी ने यह सही कहा कि इस तकनीक में दुनिया को बदलने की ताकत है, लेकिन अमेरिका की कुछ बड़ी तकनीकी कंपनियों ने सूचना संसार में अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया है। उनके एकाधिकार और उनकी मनमानी से निपटना विश्व के तमाम देशों के लिए मुश्किल हो रहा है। यदि इसी तरह का एकाधिकार एआई कंपनियों ने भी स्थापित कर लिया तो फिर समस्या गंभीर हो जाएगी। सबसे अधिक समस्या विकासशील और निर्धन देशों को होगी, जो पहले से ही चुनिंदा तकनीकी कंपनियों के वर्चस्व तले दबी हुई है। मोदी ने एआई तकनीक के संतुलित एवं विवेकसम्मत उपयोग एवं विकास की आवश्यकता को भी व्यक्त किया। क्योंकि यह उन्नत तकनीक बनाने वाली कुछ कंपनियां उसे अपने हिसाब से संचालित करती हुई भी दिख रही हैं। इस तकनीक का मनमाना इस्तेमाल न होने पाए, इसके लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय को प्रभावी कदम उठाने होंगे। यह एआई एक्शन समिट ऐसे समय हो रही है, जब चीनी कंपनी डीपसीक दुनिया को एक जबर्दस्त झटका दे चुकी है। भारत एआई की चुनौतियों एवं खतरों को लेकर सतर्क है। क्योंकि एआई द्वारा प्रस्तुत चुनौतियाँ बहुआयामी हैं और लगातार विकसित हो रही हैं। उदाहरण के लिए डीपफेक, जो डिजिटल मीडिया हैं-वीडियो, ऑडियो और चित्र-जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके संपादित और हेरफेर किया जाता है, हाइपर-रियलिस्टिक डिजिटल मिथ्याकरण को शामिल करते हैं। इसका संभावित रूप से प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने, सबूत गढ़ने और लोकतांत्रिक संस्थानों में विश्वास को कम करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। जबकि डीपफेक का इस्तेमाल चुनावों जैसे कुछ मामलों में किया गया है, उनका उपयोग विभिन्न अन्य क्षेत्रों में भी तेजी से देखा जा रहा है। डीपफेक के अलावा, एआई से जुड़े अन्य जोखिम भी हैं। इनमें गोपनीयता, पूर्वाग्रह, पारदर्शिता, जवाबदेही और दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के लिए एआई के संभावित दुरुपयोग से संबंधित मुद्दे शामिल हैं।

भारत सरकार इन मुद्दों को सलाह और विनियमों के माध्यम से नियोजित एवं नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है जो पारदर्शिता, सामग्री मॉडरेशन, सहमति तंत्र और डीपफेक पहचान पर जोर देते हैं ताकि जिम्मेदार एआई तैनाती सुनिश्चित हो और चुनावी अखंडता की रक्षा हो सके। यह एक सतत प्रयास है और जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे, इन चुनौतियों से निपटने के लिए अधिक मजबूत तंत्र के विकास के साथ सक्षम होने की अपेक्षा रहेगी। एआई विकसित होता रहेगा, नये-नये करिश्माई एवं चमत्कारी आयाम उससे जुड़ते रहेंगे और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह ऐसे तरीके से हो जो सभी के लिए सुरक्षित, नैतिक और लाभकारी हो। आवश्यक बुनियादी ढांचे, हार्डवेयर और क्लाउड कंप्यूटिंग क्षमताओं के विकास में सहायता के लिए निवेश महत्वपूर्ण है। सरकार और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग से आवश्यक पूंजी जुटाई जा सकती है। यह संयुक्त प्रयास एआई नवाचार, आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा दे सकेगा और जिससे भारत एआई क्रांति में अग्रणी बन दुनिया का नेतृत्व कर सकेगा।

इसी पहलू को रेखांकित करती है यह पेरिस की तीसरी एआई एक्शन समिट, जिसमें दुनिया भर के 90 देशों और तमाम बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आर्टिफिशल इंटेलिजेंस हमारे भविष्य का अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन किसी भी वजह से इसकी ग्रोथ को बेकाबू होने दिया गया तो उसके परिणाम खतरनाक साबित हो सकते हैं। भारत की भूमिका को खास बनाता है इसका असाधारण टैलंट पूल, इसके वे इंजिनियर और वैज्ञानिक जो नाम मात्र की लागत पर बड़े-बड़े अंतरिक्ष अभियान को अंजाम देते रहे हैं। हालांकि अभी तक इस मामले में भारत की पहल बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। बेहतर होगा कि केंद्र सरकार एक स्वतंत्र मंत्रालय बनाकर इस तकनीक को लेकर अपनी प्राथमिकता तय करे। इनोवेशन में भारत को हर जोखिम को उठाने के लिये स्वयं को सक्षम करना होगा। एआई का समुचित लाभ उठाने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। एआई के जरिये वे अनेक काम किए जा सकते हैं, जो अब तक मनुष्य करते रहे हैं, लेकिन यह ध्यान रहे कि उसमें मानवीय संवेदनाएं नहीं होतीं और वह उपलब्ध डाटा के आधार पर ही किसी नतीजे पर पहुंचती है। अब यदि डाटा ही सटीक न हो तो नतीजे भी नुकसान पैदा करने वाले हो सकते हैं। इस पर हैरानी नहीं कि अति उन्नत एआई को मानव सभ्यता के लिए संकट के रूप में भी देखा जा रहा है। इस आशंका को निर्मूल साबित करने वाले उपाय करना समय की मांग हैं और उन पर ज्यादा फोकस करना होगा।

इस तरह की तकनीक तभी लाभकारी सिद्ध होती है, जब उसका उपयोग समझदारी, नैतिकता एवं विवेकपूर्ण होता है। ज्यादा जरूरी है उसके दुरुपयोग की आशंकाओं पर प्रभावी ढंग से लगाम लगाने की स्थितियों एवं तंत्र को विकसित करने की। एआई के मामले में ऐसा इसलिए अनिवार्य रूप से करना होगा, क्योंकि यह मानव जीवन को कहीं गहराई से प्रभावित करने की क्षमता रखती है। एआई एक नई तकनीक है और बहुत से लोग उसके प्रयोग के तौर-तरीकों से अपरिचित हैं। इसीलिए यह आशंका उभरी है कि उसके कारण रोजगार का संकट पैदा हो सकता है। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नौकरियों पर एआई के प्रभाव को समझने के लिए एक व्यापक, डेटा-समर्थित अध्ययन आवश्यक है। आईएमएफ की एक रिपोर्ट ने अनुमान लगाया है कि एआई दुनिया भर में लगभग 40 प्रतिशत नौकरियों को प्रभावित करेगा, कुछ को प्रतिस्थापित करेगा और दूसरों को पूरक करेगा। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एआई अपने उपयोग के विकास के साथ नए प्रकार की नौकरियां भी पैदा करेगा। एआई पहले से ही विनिर्माण से लेकर बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवा, कृषि और शिक्षा तक सभी क्षेत्रों में बदलाव ला रहा है। उदाहरण के लिए, शिक्षा क्षेत्र में, एआई व्यक्तिगत पाठ्यक्रम, परीक्षण, सीखने के तरीके और वितरण को सक्षम कर-के भारत के सीखने के परिदृश्य को बदल रहा है। निःसंदेह यह नई तकनीक अवसर बन रही है, तकनीकी विकास का सूरज बनकर नयी समाज संरचना को बल दे रही है। यह संभावनाभरा है कि पेरिस शिखर सम्मेलन में एआई के क्षेत्र में भारत और प्रमुख देशों के बीच सामंजस्य बढ़ने के संकेत मिले, लेकिन बात तब बनेगी, जब यह मंच एआई के नियमन एवं नियोजित विकास के लिए सहमति कायम तीव्र प्रगति और व्यापक अनुप्रयोग को देखते हुए, भारत के लिए अपना स्वयं का एआई सुरक्षा संस्थान स्थापित करना अपेक्षित है। ऐसा संस्थान सुरक्षित और नैतिक एआई प्रथाओं को विकसित करने, अनुसंधान करने और एआई के उपयोग में सुरक्षा की संस्कृति को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है।

महिलाओं का सशक्तिकरण एक बहु-आयामी अवधारणा है

विजय गर्ग

महिला सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो महिलाओं और लड़कियों को रणनीतिक जीवन विकल्प बनाने और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार करने की शक्ति और नियंत्रण प्रदान करती है। इसका उद्देश्य महिलाओं को जीवन के सभी पहलुओं में अवसरों, संसाधनों और अधिकारों तक समान पहुंच प्रदान करके लैंगिक विषमताओं को खत्म करना है। महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषमताओं को समाप्त करने की प्रक्रिया से है। इस शब्द ने 19 वीं शताब्दी में प्रमुखता प्राप्त की, सशक्तिकरण के साथ शक्ति को सक्षम करने या प्रदान करने के कार्य को दशार्ता है। सदियों से, महिलाओं को दुनिया भर में कमजोर लिंग माना जाता रहा है। भारत के स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भी, महिलाओं को समान सामाजिक-आर्थिक स्थिति से वंचित रखा गया। इसे संबोधित करने के लिए, भारत सरकार और विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों दोनों ने समाज में महिलाओं के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए पहल की है। महिला सशक्तिकरण के प्रकार महिला सशक्तिकरण एक बहुआयामी अवधारणा है जिसे पांच प्रमुख प्रकारों में तोड़ा जा सकता हैः सामाजिक सशक्तिकरणः यह प्रकार महिलाओं की सामाजिक स्थिति और संबंधों को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। यह पारंपरिक पितृसत्तात्मक मानदंडों, भेदभाव और हानिकारक प्रथाओं को चुनौती देता है ताकि महिलाओं को अपने स्वास्थ्य, विवाह और जीवन शैली के बारे में स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार मिल सके। यह एक मूलभूत प्रकार है जो लड़कियों और महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्रदान करता है। आत्मविश्वास बढ़ाने, आत्मनिर्भरता में सुधार और महिलाओं को सामाजिक और राजनीतिक जीवन में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है। इसमें महिलाओं को आर्थिक संसाधनों, रोजगार और उद्यमशीलता के अवसरों तक समान पहुंच प्रदान करना शामिल है। वित्तीय स्वतंत्रता महिलाओं को अपने अधिकारों का दावा करने, अपने निर्णय लेने और अपने घर और समुदाय की आर्थिक भलाई में योगदान करने की अनुमति देती है।

राजनीतिक सशक्तिकरणः यह प्रकार सुनिश्चित करता है कि महिलाओं को राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेने का अधिकार और क्षमता हो। इसमें शासन, मतदान और सार्वजनिक कार्यालय में एक कहना शामिल है, जो उन नीतियों को आकार देने में मदद करता है जो महिलाओं के लिए फायदेमंद हैं।

मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरणः यह महिलाओं के आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के निर्माण के बारे में है। यह उन्हें सामाजिक और सांस्कृतिक वर्जनाओं को दूर करने और समाज में उनसे जो उम्मीद की जाती है उसे चुनौती देने का साहस हासिल करने में मदद करता है। महिला सशक्तिकरण को प्राप्त करने में कठिनाइयाँ प्रगति के बावजूद, महत्वपूर्ण चुनौतियां विश्व स्तर पर महिला सशक्तिकरण में बाधा डालती हैं। कुछ प्रमुख कठिनाइयों में शामिल हैंः

सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंडः गहराई से अंतर्वर्धित पितृसत्तात्मक विश्वास और सामाजिक रीति-रिवाज अक्सर महिलाओं की भूमिकाओं को निर्धारित करते हैं, उनकी स्वतंत्रता और अवसरों को सीमित करते हैं। बाल विवाह, महिला जननांग विकृति और दहेज जैसी प्रथाएं अभी भी दुनिया के कई हिस्सों में प्रचलित हैं। आर्थिक असमानताः महिलाओं को अक्सर एक महत्वपूर्ण वेतन अंतर, व्यावसायिक अलगाव और वित्तीय संसाधनों और संपत्ति के स्वामित्व तक सीमित पहुंच का सामना करना पड़ता है। ₹ाह आर्थिक असमानता उनके लिए वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना और गरीबी के चक्र से बचना मुश्किल बना देती है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच की कमीः गरीबी, सांस्कृतिक परंपराओं या प्रारंभिक विवाह के कारण लाखों लड़कियों को शिक्षा तक पहुंच से वंचित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, महिलाओं को अक्सर खराब स्वास्थ्य सुविधाओं का सामना करना पड़ता है, विशेष रूप से प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित।

लिंग आधारित हिंसाः यह एक व्यापक मुद्दा है जिसमें घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और मानव तस्करी शामिल हैं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा की उच्च दर असुरक्षा और भय की निरंतर भावना पैदा करती है, जिससे सार्वजनिक जीवन में पूरी तरह से भाग लेने की उनकी क्षमता बाधित होती है। सीमित राजनीतिक प्रतिनिधित्वः महिलाओं को अक्सर राजनीतिक नेतृत्व और निर्णय लेने वाले निकायों में कम प्रतिनिधित्व दिया जाता है। प्रतिनिधित्व की इस कमी का मतलब है कि उनकी अनूठी जरूरतों और दृष्टिकोणों को अक्सर नीति और कानून में पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया जाता है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा सबसे व्यापक मानवाधिकार उल्लंघनों में से एक है। यह महिलाओं की शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक भलाई को गंभीर रूप से प्रभावित करता है, जिससे लैंगिक समानता प्राप्त करने में बाधाएं पैदा होती हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों से 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 15.3% की वृद्धि हुई है। घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, तस्करी और ऑनर किलिंग महिलाओं की स्वतंत्रता और गरिमा को कमजोर करती रहती हैं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के प्रकार महिलाओं के खिलाफ हिंसा कई रूप लेती है, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सीमाओं को काटती है। घरेलू हिंसाः सबसे व्यापक रूपों में से एक, घरेलू हिंसा में एक अंतरंग साथी द्वारा मौखिक, गैर-मौखिक, शारीरिक, यौन, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार शामिल हैं। महिला शिशु / महिला हत्याः यह एक लड़की के बच्चे की जानबूझकर हत्या को संदर्भित करता है, या तो जन्म से पहले (सेक्स-चयनात्मक गर्भपात के माध्यम से) या जन्म के बाद, सिर्फ इसलिए कि वह महिला है।

आरक्षण: पीढ़ीगत विशेषाधिकार या वास्तविक न्याय?

डॉ सत्यवान सौरभ

भारत में आरक्षण का मुद्दा हमेशा से एक संवेदनशील और विवादास्पद विषय रहा है। यह सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और ऐतिहासिक उत्पीड़न के निवारण का एक महत्वपूर्ण उपकरण माना जाता है। परंतु जैसे-जैसे समय बीतता गया, आरक्षण की अवधारणा अपने मूल उद्देश्यों से भटकती प्रतीत होती है।

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बी.आर. गवई का बयान इस बहस को एक नई दिशा में ले जाता है, जिसमें उन्होंने कहा कि संपन्न लोगों को आरक्षण से बाहर करने का निर्णय संसद को करना चाहिए। उनका यह कथन कई सवाल खड़े करता है झ्र क्या आरक्षण का वास्तविक लाभ उस वर्ग तक पहुंच रहा है जिसके लिए यह बनाया गया था? क्या यह व्यवस्था अब सुधार और पुनर्विचार की मांग करती है?

आरक्षण का मूल उद्देश्य

आरक्षण का आरंभ भारतीय समाज में व्याप्त गहरी सामाजिक असमानताओं को समाप्त करने और सदियों से वंचित समुदायों को मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से हुआ था। यह एक ऐसा साधन था जिससे सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन को दूर कर समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिल सके। संविधान निमार्ता डॉ. भीमराव आंबेडकर ने आरक्षण को एक अस्थायी उपाय के रूप में प्रस्तुत किया था, ताकि दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों को न्याय और अवसर मिल सके। उनका उद्देश्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना था जहाँ जातीय भेदभाव और सामाजिक उत्पीड़न का कोई स्थान न हो। यह केवल सरकारी नौकरियों और शिक्षा तक सीमित नहीं था, बल्कि एक समग्र सामाजिक सुधार की दिशा में एक साहसिक कदम था। लेकिन, धीरे-धीरे यह व्यवस्था उन परिवारों के लिए एक पीढ़ीगत विशेषाधिकार बनती जा रही है जो पहले ही सशक्त हो चुके हैं। न्यायमूर्ति गवई का यह कहना कि जब एक व्यक्ति क्अर या क्हर बन जाता है, तो उसके बच्चे उसी समाज की कठिनाइयों का सामना नहीं करते हैं, एक महत्वपूर्ण सत्य की ओर इशारा करता है। एक अधिकारी का परिवार उच्च शिक्षा, बेहतर जीवनशैली और संसाधनों तक सहज पहुंच के कारण वास्तविक वंचितों से कोसों दूर हो जाता है। यह स्थिति केवल सरकारी सेवाओं में ही नहीं, बल्कि निजी क्षेत्र, उच्च शिक्षा संस्थानों और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों में भी देखी जा सकती है।

हमेशा जीवन बोलना चाहिए, मार्क्स नहीं

परीक्षा पर चर्चा 2018 से एक वार्षिक कार्यक्रम रहा है। इस कार्यक्रम में, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश के अभिभावकों, शिक्षकों और छात्रों से बातचीत करते हैं। वे प्रवेश और बोर्ड परीक्षाओं को सहज और आसान तरीके से कैसे हल किया जाए, इस पर सलाह देते हैं। इस कार्यक्रम के प्रतिभागियों को एक प्रतियोगिता के माध्यम से चुना जाता है। इस कार्यक्रम में भाग लेने का मौका मिलने के अलावा, प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रधानमंत्री से आमने-सामने बात करने का भी अवसर मिलता है। परीक्षा पर चर्चा का उद्घाटन संस्करण 16 फरवरी, 2018 को हुआ था। 29 जनवरी, 2024 को होने वाले 7वें संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पर्याप्त नींद लें और रील देखने में समय बर्बाद न करें। 2025 में आयोजित होने वाले आठवें पीपीसी में इस साल परीक्षा से सम्बंधित तनाव को कम करने पर विशेष जोर दिया गया था। परीक्षा पर चर्चा 2025 कार्यक्रम में सद्गुरु (आध्यात्मिक नेता) , दीपिका पादुकोण (अभिनेता) , विक्रांत मैसी (अभिनेता) , मैरी कॉम (ओलंपिक चैंपियन, बॉक्सर) और अवनी लेखरा (पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता) जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति शामिल हुए। इन प्रतिष्ठित अतिथियों ने तनाव प्रबंधन, उद्देश्यों को पूरा करने और प्रेरणा बनाए रखने पर अपने अनुभव और व्यावहारिक विचार साझा किए। 10 फरवरी, 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पर चर्चा 2025 के आठवें संस्करण के दौरान छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ बातचीत की। यह वार्षिक आयोजन छात्रों को परीक्षा की चिंता, करियर प्लानिंग और व्यक्तिगत विकास जैसे मुद्दों पर बात करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इस वर्ष के आयोजन के लिए 330 करोड़ से अधिक छात्रों, 2071 लाख शिक्षकों और 551 लाख अभिभावकों ने पंजीकरण कराया है, जो देश के युवाओं पर इस पहल के निरंतर प्रभाव को दशार्ता है। पीएम मोदी के अनुसार, कक्षा 10 और 12 में 40-50% छात्र असफल होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह उनका अंतिम उद्देश्य है। शैक्षणिक और व्यक्तिगत सफलता और असफलता के बीच अंतर को पहचानना महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने क्रिकेट खिलाड़ियों का उदाहरण दिया, जो दिन के अंत में अपनी गलतियों पर विचार करते हैं और उनमें सुधार करते हैं; छात्रों को भी ऐसा ही करना चाहिए। उनके अनुसार, आपका जीवन वही है जो आपके अंक बताते हैं, न कि आप। पीएम ने छात्रों को दबाव को नजरअंदाज करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि एक बल्लेबाज की तरह जो स्टेडियम के शोर और नारों को नजरअंदाज कर गेंद पर ध्यान केंद्रित करता है, छात्रों को भी तनाव के बजाय अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन बच्चों का क्या होता है जो 30 से 40 प्रतिशत की दर से स्कूल में फेल हो जाते हैं? देखिए, असफलता जीवन के अंत का संकेत नहीं है। आप जीवन में सफल होना चाहते हैं या किताबों के माध्यम से, यह आप पर निर्भर करता है। अपनी सभी असफलताओं को शिक्षण के अवसर में बदलना जीवन में सफलता प्राप्त करने की एक रणनीति है। अपनी गलतियों को अपने शिक्षण के क्षण बनाएँ। जीवन केवल परीक्षा नहीं है। इसे समग्र रूप से देखा जाना चाहिए। हमें कुछ खासियतें देने के अलावा, भगवान ने हमारी कुछ खामियाँ भी रखी हैं। खूबियों पर ध्यान दें। आपसे यह नहीं पूछा जाएगा कि आपको 10वीं और 12वीं कक्षा में कितने ग्रेड मिले। यह जीवन होना चाहिए, न कि अंक। रटने की शिक्षा के विपरीत, प्रधान मंत्री मोदी ने समग्र शिक्षा और रचनात्मक शिक्षा के महत्त्व पर जोर दिया। छात्रों से सॉफ्ट स्किल सीखने और पाठ्येतर गतिविधियों में भाग लेने का आग्रह किया गया। प्रधानमंत्री ने छात्रों को सलाह दी कि परीक्षाओं को सीखने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि बोझ के रूप में। उन्होंने सलाह दी कि छात्रों को ग्रेड से ज्यादा ज्ञान को प्राथमिकता देनी चाहिए। अच्छा व्यवहार, अनुशासन और अभ्यास-अधिकारों के लिए शोर मचाना नहीं-नेतृत्व की पहचान हैं। सफल शिक्षा के लिए स्वस्थ भोजन और पर्याप्त नींद के महत्त्व पर बल दिया। छात्रों से मानसिक स्वास्थ्य के लिए बाहर समय बिताने और शारीरिक गतिविधि के स्तर को बढ़ाने का आग्रह किया। पीएम मोदी ने छात्रों को सलाह दी कि वे परीक्षाओं से डरने के बजाय इसे एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने के अवसर के रूप में देखें। उन्होंने दावा किया कि परिवार और सामाजिक वातावरण कभी-कभी छात्रों पर दबाव डाल सकते हैं, जो अवांछनीय है। परिवार के सदस्यों या रिश्तेदारों का यह दबाव कि बोर्ड परीक्षाएँ बहुत जरूरी हैं, छात्रों को अत्यधिक चिंतित और तनावग्रस्त बना देता है।

आपका जीवन एक परीक्षा के साथ समाप्त नहीं होता है।

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में डकैतों ने वाहनों पर की गोलीबारी, 10 लोगों को किया अगवा

एजेंसी

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हथियारबंद डकैतों ने वाहनों पर हमला कर 10 लोगों को अगवा कर लिया। यह वारदात बुधवार देर रात रहीम यार खान जिले के भोंग शरीफ के पास एम-5 मोटर-वे पर हुई। इस दौरान डकैतों ने गुजर रहे वाहनों को निशाना बनाया। गोलीबारी में कई लोग घायल भी हो गए। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर में पुलिस के हवाले से बताया गया कि घातक हथियारों से लैस डकैतों के एक समूह ने कारों, दो बसों, ट्रकों और ट्रेलरों पर गोलीबारी की। गोलीबारी में एक महिला और एक बच्चे सहित चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें रहीम यार खान के शेख जायद अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद सुरक्षा बलों ने मोटर-वे पर यातायात अस्थायी रूप से रोक दिया। पुलिस ने पुष्टि की कि डकैत 10 लोगों को अगवा कर अपने साथ ले गए हैं। इनमें यात्री और ट्रक ड्राइवर शामिल हैं। पुलिस सूत्रों ने पुष्टि की है कि गोलीबारी के बाद हमलावर नदी किनारे के कच्चा इलाकों की ओर भाग गए। कई ट्रक मोटरवे पर ही छोड़ दिए गए, और उनके चालक दल के सदस्य लापता हो गए। इससे कुछ दिन पहले रहीम यार खान पुलिस ने कुख्यात इंधर गिरोह के ठिकानों पर ड्रोन हमले किए थे।

नमाज के बाद मचा हंगामा : सूफी संत की कब्र तोड़ी

ढाका। बांग्लादेश में दो बड़ी हिंसक वारदातें सामने आईं। उग्र कट्टरपंथियों ने सूफी संत नूरा पगला की मजार से शव निकालकर आग के हवाले कर दिया। वहीं, राजधानी ढाका में जातीयः बांग्लादेश दो भयावह घटनाओं से दहल उठा। पहली वारदात में इस्लामिक कट्टरपंथियों ने एक सूफी संत की मजार को अपवित्र कर उनके शव को आग के हवाले कर दिया। दूसरी ओर, जातीय पार्टी के दफ्तर में भीषण आगजनी की गई। इन घटनाओं ने पूरे देश में दहशत और तनाव का माहौल पैदा कर दिया है। गौरतलब है कि पिछले साल हुए तख्तापलट के बाद से बांग्लादेश में लगातार हिंसा बढ़ रही है, जहां खासकर मुस्लिम कट्टरपंथी अल्पसंख्यक समुदायों को अपना निशाना बना रहे हैं। पश्चिमी राजबारी जिले में जुमे की नमाज़ के बाद हालात अचानक बिगड़ गए। कुछ मुस्लिम कट्टरपंथियों ने सूफी दरवेश नूरा पगला की कब्र पर हमला कर दिया। नूरा पगला का निधन करीब दो हफ्ते पहले हुआ था। हमलावरों ने उनकी कब्र खोदकर शव को बाहर निकाला और आग के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, उनकी दरगाह को भी तोड़फोड़ कर नुकसान पहुंचाया गया। इस घटना के बाद नूरा पगला के समर्थकों और हमलावरों के बीच हिंसक झड़प छिड़ गई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और 100 से अधिक लोग घायल हो गए।

रूस ने व्हाट्सएप को निशाना बनाया, इंटरनेट ब्लैकआउट बढ़ने पर नया 'सुपर-ऐप' किया लांच

मॉस्को। रूस के मीडिया नियामक रोस्कोम्नाडज़ोर द्वारा अगस्त के मध्य में लगाए गए नए प्रतिबंधों का लाखों रूसी नागरिकों को सामना करना पड़ रहा है। ये प्रतिबंध रूस में सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग एप व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए की जाने वाली कॉल पर लगाए गए हैं। बीबीसी के मुताबिक इसी समय रूसी फर्म ने मैक्स नाम से एक नए राष्ट्रीय मैसेंजर एप को लांच किया है, जिसे क्रेमलिन नियंत्रित करता है। यदि देश में व्हाट्सएप और टेलीग्राम के मासिक उपयोगकर्ताओं की आंकड़ों की बात करें तो कुल 14.30 करोड़ की आबादी में से व्हाट्सएप और टेलीग्राम के मासिक उपयोगकर्ताओं की संख्या क्रमशः 9.7 और नौ करोड़ होने का अनुमान है। व्हाट्सएप की मालिकाना कंपनी मेटा को रूस में एक चरमपंथी संगठन घोषित किया गया है। यह एप विशेष रूप से बुजुर्ग लोगों के बीच खासा लोकप्रिय है क्योंकि इसमें पंजीकरण करना और इसका उपयोग करना बहुत आसान है। रूस के कुछ हिस्सों में खासकर दूरदराज और कम कनेक्टिविटी वाले इलाकों में व्हाट्सएप दोस्तों और सहकर्मियों के साथ चैटिंग से कहीं बढ़कर है। मोबाइल ब्राउज़िंग जब कभी-कभी बहुत धीमी हो जाती है, तो लोग स्थानीय मामलों में एक-दूसरे से बात करने, टैक्सी बुक करनेऔर खबरें साझा करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं।

अमेरिका और भारत के बीच तनावः ट्रम्प के मंत्री ने दी भारत को चेतावनी, रखी तीन शर्तें

वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका में ट्रम्प प्रशासन के एक वरिष्ठ मंत्री ने भारत को एक कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे चएक या दो महीने' के भीतर कुछ मुद्दों पर माफी मांगनी होगी। मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बयान दिया, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। यह चेतावनी हाल ही में हुए एक अज्ञात व्यापारिक या कूटनीतिक विवाद से जुड़ी हुई मानी जा रही है। मंत्री ने भारत से माफी मांगने के लिए तीन शर्तें भी रखी हैं। पहली शर्त यह है कि भारत को एक विशेष व्यापारिक समझौते में अमेरिका को प्राथमिकता देनी होगी। दूसरी शर्त में एक महत्वपूर्ण सुरक्षा मामले में भारत से सहयोग की मांग की गई है। तीसरी और सबसे कठोर शर्त यह है कि भारत को एक हालिया घटना के लिए सार्वजनिक तौर पर खेद व्यक्त करना होगा। इस बयान के बाद भारत सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि, कूटनीतिक हलकों में इस बयान को बेहद आपत्तिजनक और कूटनीतिक प्रोटोकॉल का उल्लंघन माना जा रहा है।

ट्रंप के रूख में बड़ा बदलाव, बोले भारत के साथ रिश्ते अहम, मोदी अच्छे दोस्त

एजेंसी

वाशिंगटन। अमेरिका द्वारा भारत पर भारी टैरिफ लगाये जाने के बाद दोनों देशों में चल रही तनातनी के बीच पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत के साथ संबंधों को विशेष और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अच्छा दोस्त बताये जाने वाले बयान और उस पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सकारात्मक जवाब के बाद इस मुद्दे के समाधान की उम्मीद बढ गयी है। श्री ट्रंप ने अपने पहले दिये गये बयान से बारह घंटे में ही पलटते हुए व्हाइट हाउस में भारत के साथ रिश्तों को बेहद खास बताते हुए कहा था कि वह और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि वह महान प्रधानमंत्री हैं। दोनों देशों के संबंधों के बारे में श्री ट्रंप ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी प्रधानमंत्री मोदी के

साथ अच्छी बनती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने साथ ही यह भी कहा कि लेकिन उन्हें भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने को लेकर नाराजगी भी है। साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच कभी-कभी इस तरह की बातें हो जाती हैं।

श्री मोदी ने शनिवार को इसके जवाब पर बेहद सकारात्मक प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि वह श्री ट्रंप की भावनाओं का सम्मान करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा , राष्ट्रपति ट्रम्प की भावनाओं और हमारे संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन की हम तहे दिल से सराहना करते हैं और उनका पूर्ण समर्थन करते हैं। भारत और अमेरिका के बीच एक अत्यंत सकारात्मक और दूरदर्शी व्यापक एवं वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। उल्लेखनीय है कि श्री ट्रंप ने इससे पहले चीन में प्रधानमंत्री मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात के बाद कहा था कि लगता है हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। लेकिन बारह घंटे के अंदर ही श्री ट्रंप ने अपने रूख को बदलते हुए भारत के साथ रिश्तों को अहम बताया और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की भी प्रशंसा की और कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है।

एमके स्टालिन ने ऑक्सफ़ोर्ड में पेरियार के चित्र का अनावरण किया

एजेंसी

लंदन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने ब्रिटेन में लंदन स्थित प्रसिद्ध ऑक्सफ़ोर्ड विश्वविद्यालय के सेंट एंथनी कॉलेज में गुरूवार को पेरियार के चित्र का अनावरण किया। यह अनावरण दिवंगत नेता के स्वाभिमान आंदोलन के सौ साल पूरा होने के उपलक्ष्य में स्वाभिमान आंदोलन और उसकी विरासत 2025 विषय पर आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी के अंतर्गत किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर अपने संबोधन में स्टालिन ने चित्र के अनावरण को अपने जीवन का अविस्मरणीय क्षण बताते हुए कहा कि पेरियार के समानता के सिद्धांत सीमाओं से परे हैं और वे समूची मानवता से जुड़े हैं।

इस अवसर पर उन्होंने निचले तबकों के समुदायों के उत्थान के लिए विश्वस्तर पर आरक्षण की नीतियां अपनाए जाने का आह्वान करते हुए कहा कि इससे पेरियार की सामाजिक न्याय की अवधारणा पूरी हो सकेगी। मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु में महिलाओं को संपत्ति का समान अधिकार है और राज्य के मंदिरों में सभी धर्मों के लोग पुजारी बन सकते हैं। राज्य ने ऐसा कर समाज सुधार आंदोलन को राजनीतिक बल प्रदान किया है। इस अवसर पर उन्होंने दो पुस्तकों द द्रविड़ियन पाथवे और द कैम्ब्रिज कम्पैनियन टू पेरियार का भी विमोचन किया। बाद में सोशल मीडिया मंच पर अपने पोस्ट में स्टालिन ने चित्र के अनावरण को गर्व का क्षण बताते हुए खुद को पेरियार का पोता करार दिया। उल्लेखनीय है कि स्टालिन एक सप्ताह के विदेश दौरे पर हैं। इससे पहले वह जर्मनी में थे। उनकी विदेश यात्रा का लक्ष्य राज्य के लिए विदेशी निवेश की संभावनाएं तलाशना है।

वेनेजुएला ने 48 घंटे में दूसरी बार अमेरिकी विध्वंसक पोत के आसपास सैन्य विमान उड़ाए

एजेंसी

वाशिंगटन (अमेरिका)। वेनेजुएला ने दक्षिण अमेरिका के पास अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में 48 घंटे में दूसरी बार विध्वंसक पोत यूएसएस जेसन डनहम के आसपास सैन्य विमान उड़ाए हैं। रक्षा विभाग के कई अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने इस कार्रवाई को मुहावरे की भाषा में मुर्गी का खेल बताया। सीबीएस न्यूज की खबर के अनुसार, रक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि यह एफ-16 लड़ाकू विमान था। यह गुरुवार रात किसी समय डनहम के ऊपर से उड़ा। यह अज्ञात है कि विमान हथियारों से लैस था या नहीं।अधिकारियों ने बताया कि एजिस निर्देशित मिसाइल विध्वंसक डनहम ने कोई हमला नहीं किया। पेंटागन ने पहली घटना पर इसे बेहद भड़काऊ कदम बताया था। पेंटागन ने कहा था, हमारे मादक-आतंकवाद विरोधी अभियानों में हस्तक्षेप करने के लिए ऐसा किया गया। डनहम उन अमेरिकी युद्धपोतों में से एक है जिन्हें हाल के सप्ताहों में इस क्षेत्र में भेजा गया है। पेंटागन का कहना है कि इन्हें आपराधिक संगठनों और मादक पदार्थ-आतंकवाद को निशाना बनाने के लिए तैनात किया गया है। राष्ट्रपति

डोनाल्ड ट्रंप ने टिप्पणी की, मैं कहूंगा कि वे मुश्किल में पड़ जाएंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने पत्रकारों से एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर वेनेजुएला ने फिर से अमेरिकी नौसेना के जहाजों के ऊपर से जेट उड़ाए तो बहुत बुरा हो सकता है। ट्रंप ने रक्षा सचिव पीट हेगसेथ और ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन केन से भी बात की है। व्हाइट हाउस ने मंगलवार को घोषणा की थी कि अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला से कथित तौर पर ड्रग तस्करी करने वाली एक नाव पर हमला किया। इस हमले में 11 लोग मारे गए। ट्रंप प्रशासन ने कहा कि नाव का संचालन ट्रेन डी अरागुआ गिरोह कर रहा था। अमेरिकी योजनाओं से परिचित एक सूत्र ने पुष्टि की कि अमेरिका ड्रग कार्टेलों को निशाना बनाने के लिए कैरिबियन में 10 एफ-35 लड़ाकू विमान भेज रहा है।

जॉर्जिया में हुंडई के संयंत्र से दक्षिण कोरियाई बैटरी निर्माता के 475 कर्मचारी गिरफ्तार

एजेंसी

वाशिंगटन (अमेरिका)। आव्रजन अधिकारियों ने दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य जॉर्जिया स्थित हुंडई के एक संयंत्र से 475 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह सभी एक प्रमुख दक्षिण कोरियाई बैटरी निर्माता के कर्मचारी है। अमेरिकी अधिकारियों ने इसे एक ही स्थान पर सबसे बड़ा होमलैंड सुरक्षा प्रवर्तन अभियान बताया है।

द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के अनुसार, जॉर्जिया में होमलैंड सुरक्षा जांच के प्रभारी विशेष एजेंट स्टीवन श्रैंक ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि एजेंटों ने गुरुवार को जॉर्जिया के एलाबेल में सवाना के पास हुंडई के इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी संयंत्र के निर्माण स्थल से 475 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें से अधिकांश दक्षिण कोरियाई नागरिक हैं। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई कई महीनों तक चली एक जांच का परिणाम है। विशेष एजेंट श्रैंक ने कहा कि गिरफ्तार किए गए कर्मचारी या तो अवैध रूप से अमेरिका में थे या गैरकानूनी तरीके से काम कर रहे थे। इस अभियान का उद्देश्य कानून का पालन करने वाले व्यवसायों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना है। यह कर्मचारी बैटरी निर्माता एलजी एनर्जी सॉल्यूशन के हैं। यह कंपनी हुंडई मोटर ग्रुप के साथ इस संयंत्र का सह-स्वामित्व रखती है। हुंडई ने स्वीकार किया है कि उसकी सहयोगी कंपनियों के कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया है। मगर इनमें हुंडई का एक भी कर्मचारी नहीं है। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की कि हिरासत में लिए गए लोगों में दक्षिण कोरियाई नागरिक भी शामिल हैं, हालांकि यह नहीं बताया कि कितने लोग हिरासत में हैं। इस बीच अटलांटा के आव्रजन वकील चार्ल्स कुक ने बताया कि उनके दो मुवक्किल वीजा छूट कार्यक्रम के तहत देश में थे। उन्हें भी पकड़ा गया है। एशियन अमेरिकंस एडवांसिंग जस्टिस के अटलांटा कार्यालय के संचार निदेशक जेम्स वू ने कहा कि वह पूरे दिन जॉर्जिया भर के दक्षिण कोरियाई निवासियों से फोन पर बात करते रहे। वू ने कहा, लोग सदमे में हैं। कूटनीतिज्ञों का मानना है कि राष्ट्रपति ट्रंप के इस अभियान ने दक्षिण कोरिया में कूटनीतिक चिंता पैदा कर दी है। एक हफ्ते पहले ही ट्रंप ने व्हाइट हाउस में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग की मेजबानी की थी। इस दौरान दक्षिण कोरियाई नेता ने बैटरी निर्माण सहित संयुक्त राज्य अमेरिका में अतिरिक्त 150 अरब डॉलर का निवेश करने का वादा किया था।

जॉर्जिया के गवर्नर और रिपब्लिकन ब्रायन केम्प ने कहा कि 7.6 अरब डॉलर की हुंडई ई.वी. फैक्टरी को राज्य के इतिहास की सबसे बड़ी आर्थिक विकास परियोजना के रूप में प्रचारित किया गया है। इस अभियान के कारण के निर्माण कार्य रुक गया।

अमेरिका अगले साल जी-20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी ट्रंप के गोल्फ कोर्स में करेगा

एजेंसी

वाशिंगटन (अमेरिका)। अमेरिका अगले साल 2026 में विश्व नेताओं के समूह-20 (जी-20) के शिखर सम्मेलन की मेजबानी राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप के फ्लोरिडा के डोरल स्थित गोल्फ कोर्स और स्पा में करेगा। ट्रंप ने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में मियामी में जी-20 सम्मेलन आयोजित करने के अपने निर्णय की घोषणा की। सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रप ने शिखर सम्मेलन की तैयारियों का जिम्मा राष्ट्रीय आर्थिक परिषद के निदेशक केविन हैसेट को सौंपा है। राष्ट्रपति ने कहा कि वित्तमंत्री स्कॉट बेसेंट इस सम्मेलन का एजेंडा तैयार कर रहे हैं। इसके बाद व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि ट्रंप डोरल में इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी लागत पर करेंगे। विदेश विभाग या किसी विदेशी सरकार से कोई लाभ नहीं लेंगे। यह सम्मेलन 14-15 दिसंबर, 2026 को आयोजित किया जाएगा।

ट्रंप ने 150 मिलियन डॉलर में खरीदा था

ट्रंप ने 2020 में इस रिसॉर्ट में जी-7 शिखर सम्मेलन आयोजित करने की योजना बनाई थी। व्यापक आलोचना के बाद उन्होंने यह विचार त्याग दिया। अंततः, कोविड-19 महामारी की शुरुआत के कारण इस सम्मेलन को रद्द कर दिया गया और वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया। यह रिसॉर्ट ट्रंप ने 2012 में 150 मिलियन डॉलर में खरीदा था।

चार गोल्फ कोर्स हैं

यह पहली बार 1960 के दशक में खुला था। मेट्रो मियामी के घनी आबादी वाले इलाके में स्थित यह मियामी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के उड़ान मार्ग के नीचे स्थित है। इसमें चार गोल्फ कोर्स, 48,000 वर्ग फीट का एक स्पा, 125 फीट की स्लाइड वाला एक विशाल पूल और 24,000 वर्ग फीट से अधिक का एक बॉलरूम शामिल है। मियामी के मेयर फ्रांसिस सुआरेज़, ट्रंप की घोषणा के समय ओवल ऑफिस में मौजूद रहे। जी-20 एक आर्थिक मंच है, जिसमें 19 देश और दो अन्य समूह यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ शामिल हैं, जो दुनिया की अधिकांश सबसे बड़ी विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। जी-20 वेबसाइट के अनुसार, सदस्य देशों की वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 85फीसद और वैश्विक व्यापार में 75फीसद से अधिक की हिस्सेदारी है। यह जी-7, जिसमें अमेरिका, कनाडा, जापान और अन्य यूरोपीय शक्तियां शामिल हैं की तुलना में बड़ा और भौगोलिक रूप से अधिक विविध है।

प्रधानमंत्री ओली ने चीन की यात्रा से लौटने के बाद लिपुलेख के मुद्दे पर दी सफाई

एजेंसी

काठमांडू। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने चीन की यात्रा से लौटने के बाद लिपुलेख के मुद्दे पर सफाई दी है।उन्होंने कहा कि चीन भ्रमण के दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भारत और चीन के बीच हुए उस व्यापार समझौते के बारे में स्पष्ट रूप से बात की है, जिसमें लिपुलेख की भूमि का उपयोग करके व्यापार करने की बात का उल्लेख है। प्रधानमंत्री ओली ने यह बयान इसलिए दिया है, क्योंकि चीनी राष्ट्रपति के साथ मुलाकात के दौरान लिपुलेख का मुद्दा उठाए जाने पर आशंका व्यक्त करते हुए नेपाल के विपक्ष की ओर से सवाल खड़ा किया गया। प्रधानमंत्री ओली ने आज शुरू हुए पार्टी के विधान सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में जोर देकर कहा कि वे विदेशों की यात्रा के दौरान हमेशा अपने स्पष्ट विचार रखते हैं, जिससे राष्ट्र के हितों को लाभ हो।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ औपचारिक वार्ता में मैंने अन्य बातों के अलावा यह स्पष्ट कर दिया है कि लिपुलेख पर भारत और चीन के बीच समझौते का उपयोग दोनों देशों को हमारे क्षेत्र के माध्यम से व्यापार करने की अनुमति देने के लिए नहीं किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि यह मामला रिकॉर्डेड है। यह ऑडियो में है, यह वीडियो में है, यह नोट्स में भी है। उन्होंने कहा कि चीनी राष्ट्रपति ने भी कूटनीतिक समाधान की मांग की है, क्योंकि यह भारत और नेपाल के बीच का मामला है। प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि किसी भी राष्ट्रीय संप्रभुता को कमज़ोर नहीं होने देने के लिए चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि वह नेपाल की चिंता को जायज मानते हैं और इसका पूरा समर्थन करते हैं। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने कहा कि यह भारत और नेपाल के बीच का आंतरिक मामला है और उन्हें उम्मीद है कि दोनों देश इसे बातचीत के ज़रिए सुलझा लेंगे।

पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के आग्रह को ठुकराया, कहा- नहीं रुकेगा अफगान शरणार्थियों का निर्वासन

एजेंसी

काबुल। पाकिस्तान ने अफगान शरणार्थियों के मौजूदा निर्वासन को निलंबित करने के संयुक्त राष्ट्र के आह्वान को खारिज कर दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कठोर रुख अपनाते हुए कहा है कि संघीय सरकार के फैसले में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होगा।

खामा प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शफकत अली खान ने पत्रकारों को बताया कि निर्वासन नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है और इस प्रक्रिया को स्थगित नहीं किया जाएगा। इससे पहले, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त फ़िलिपो ग्रांडी ने अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में आए विनाशकारी भूकंप का हवाला देते हुए इस्लामाबाद से निर्वासन रोकने का

आग्रह किया था। अफगानिस्तान में मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत रिचर्ड बेनेट ने भी पाकिस्तान से निष्कासन में देरी करने की अपील की। इसके जवाब में पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि निर्वासन तो जारी रहेगा, लेकिन देश कानूनी रूप से प्रवेश करने के इच्छुक अफगानों के लिए उदार वीजा नीति बनाए रखेगा। पाकिस्तान ने बिना दस्तावेज वाले अफगान शरणार्थियों और जिनके अस्थायी निवास परमिट की अवधि समाप्त हो गई है, उनके लिए स्वेच्छा से देश छोड़ने की समय सीमा 1 सितंबर तय की थी। मानवाधिकार समूहों और शरणार्थी अधिवक्ताओं ने पाकिस्तान की सामूहिक निष्कासन योजना की बार-बार आलोचना की है। पर्यवेक्षकों ने चेतावनी दी है कि संयुक्त राष्ट्र की अपीलों की अनदेखी करने से पाकिस्तान के अंतरराष्ट्रीय संबंधों में और तनाव पैदा हो सकता है। साथ ही संघर्ष और प्राकृतिक आपदाओं के कारण पहले से ही विस्थापित अफगान शरणार्थियों के लिए मानवीय संकट और भी बदतर हो सकता है।

बलोचिस्तान में ईरान सीमा के पास पाकिस्तान के दो सुरक्षाकर्मियों की गोली मारकर हत्या

एजेंसी

क्वेटा (बलोचिस्तान)। पाकिस्तान के प्रांत बलोचिस्तान में ईरान की सीमा के पास केच जिले के मांड इलाके में हुए एक सशस्त्र हमले में दो सुरक्षाकर्मी मारे गए। अधिकारियों के अनुसार, यह हमला कोह-पुशात बाजार में हुआ। सशस्त्र हमलावरों ने मोटरसाइकिल सवार सुरक्षाकर्मियों पर घात लगाकर गोलीबारी की।

गोलीबारी में दोनों की मौके पर मौत हो गई।डान अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, लेवी बलों और अन्य सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत कार्रवाई कर इलाके को घेर लिया और शवों को पास के एक चिकित्सा केंद्र में पहुंचाया। मारे गए सुरक्षा कर्मचारियों की पहचान अब्दुल अजीज और जमील अहमद के रूप में हुई है। हमले के समय दोनों सादे कपड़ों में थे। द बलोचिस्तान पोस्ट के अनुसार, इस हमले की फिलहाल किसी भी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है।

गाजा में इजराइल का हमलाः हमास के ठिकानों पर तबाही, गगनभेदी इमारत ध्वस्त

एजेंसी

गाजा/यरुशलम। इजराइल ने गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों को निशाना बनाकर एक बड़ा हवाई हमला किया है। इस हमले में एक गगनभेदी इमारत को ध्वस्त कर दिया गया, जिसके बारे में इजराइल का कहना है कि इसका इस्तेमाल हमास

अपने कमांड सेंटर के तौर पर कर रहा था। इस हमले के बाद पूरे इलाके में तबाही का मंजर देखा गया है। हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, इजराइल के इस हमले में कम से कम 27 लोगों की मौत हुई है और कई अन्य घायल हुए हैं। मरने वालों में लड़ाकों के अलावा आम नागरिक भी शामिल हैं। इजराइल ने कहा है कि वह उन ठिकानों को निशाना बना रहा है, जहाँ से हमास उसके नागरिकों पर रॉकेट हमले करता है। इजराइल और हमास के बीच हुई इस झड़प के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव चरम पर है। गाजा में रहने वाले लोगों में डर का माहौल है, क्योंकि उन्हें और हमलों की आशंका है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है ताकि हिंसा को और बढ़ने से रोका जा सके।

हिजबुल से द रेजिस्टेंस फ्रंट तक, पाकिस्तान के लोकल टेररिस्ट नैरेटिव की खुली पोल

एजेंसी

नई दिल्ली । पाकिस्तान लंबे समय से कश्मीर मुद्दे को स्थानीय बनाने की कोशिश करता रहा है। पाकिस्तान ने हिजबुल मुजाहिदीन को एक स्थानीय आतंकवादी संगठन के इरादे से बनाया था। हिजबुल मुजाहिदीन के पतन के बाद उसने लश्कर-ए-तैयबा के लिए एक प्रॉक्सी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) बनाया। पाकिस्तान कई दशकों से यही चाहता रहा है कि स्थानीय लोग जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में शामिल हों। उसकी मंशा इस बात का फायदा उठाकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना से बचना था कि स्थानीय लोग कश्मीर को भारत से अलग करना चाहते हैं और इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। हालांकि, भारतीय एजेंसियां हमेशा पाकिस्तान के इस झांसे को बेनकाब करने में कामयाब रही हैं। हाल ही में पहलगाम हमले में भी राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने साफ शब्दों में कहा था कि हमलावर पाकिस्तान से थे और पूरा हमला इस्लामाबाद समर्थित था। अब एक प्रमुख कश्मीरी गैर-सरकारी संगठन, 'सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन' की एक विस्तृत रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जम्मू-कश्मीर में 60 प्रतिशत अचिह्नित कब्रें विदेशी आतंकवादियों की हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 30 प्रतिशत कब्रें स्थानीय आतंकवादियों की हैं। हालांकि, सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह है कि सिर्फ 0.2 प्रतिशत कब्रें (9) नागरिकों की हैं। यह रिपोर्ट दो प्रमुख मुद्दों को सुलझाती है। पहला, कश्मीर में स्थानीय लोगों की तुलना में पाकिस्तानी आतंकी ज्यादा सक्रिय थे। दूसरा, कई लोगों ने नागरिकों की व्यापक हत्याओं के दावों को भी खारिज कर दिया है।

'अनरेवेलिंग द ट्रुथः ए क्रिटिकल स्टडी ऑफ अनमार्क्ड एंड अनआइडेंटिफाइड ग्रेव्स इन कश्मीर वैली' शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि 2,493 कब्रें विदेशी आतंकवादियों की हैं, जबकि 1,208 स्थानीय लोगों की हैं। 9 कब्रें नागरिकों की हैं, जबकि 70 कब्रें 1947 के युद्ध के कबायली हमलावरों की हैं। पाकिस्तान लंबे समय से यह दिखाने का एजेंडा चला रहा है कि स्थानीय लोग ही आतंकवादी हमले कर रहे हैं। उसने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपने गुर्गों के जरिए यह कहानी गढ़ने की भी कोशिश की है कि जम्मू-कश्मीर में नागरिकों की सामूहिक हत्याएं हो रही हैं। इन लोगों ने यह भी कहा कि नागरिक मारे जा रहे हैं और इसे अज्ञात कब्रों से जोड़ा गया। हालांकि, रिपोर्ट इस मिथक को तोड़ती है।'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान पाकिस्तान का 'फेक नैरेटिव' अपने चरम पर था। प्रथम फील्ड मार्शल ने दावा किया कि भारत ने ही पाकिस्तान से ऑपरेशन रोकने का अनुरोध किया था। पाकिस्तान ने झूठ फैलाने के लिए आधिकारिक चैनलों और सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। इसका उद्देश्य भारतीय नागरिकों में दहशत और अंतरराष्ट्रीय समुदाय में भारत की कार्रवाई को लेकर भ्रम पैदा करना था। पाकिस्तान ने भारत में सिखों को नाराज करने की भी कोशिश की, जब उसने झूठा दावा किया कि भारत ने पाकिस्तान स्थित ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर हमला किया था। पाकिस्तान के इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने तो यहां तक कह दिया कि भारत ने अमृतसर पर मिसाइलें दागी थीं। भारत हमेशा से पाकिस्तान के झांसे को बेनकाब करने में कामयाब रहा है, लेकिन ऐसी रिपोर्टों और एनआईए की हालिया जांच का इस्तेमाल नई दिल्ली के दृष्टिकोण को सामने लाने के लिए किया जाएगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों का कहना है कि जिन कब्रों के बारे में पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, उनसे जुड़ी यह रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने इस्लामाबाद को बेनकाब करने में मददगार साबित होगी।

शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी 13 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंची

एजेंसी

नई दिल्ली। वैश्विक दबाव और टैरिफ संबंधी आशंकाओं की वजह से विदेशी निवेशक इस साल लगातार घरेलू शेयर बाजार में बिकवाली करके अपना पैसा निकालने में लगे हुए हैं। इस वजह से बाजार में उनकी हिस्सेदारी भी लगातार कम हो रही है। अगस्त के महीने में विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी घटकर 13 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। घरेलू संस्थागत निवेशकों की हिस्सेदारी अभी तक सबसे ऊंचे स्तर पर है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के आंकड़ों के अनुसार अगस्त के महीने में विदेशी निवेशकों की गई बिकवाली के चलते अब भारतीय शेयर बाजार में फॉरेन पोर्टफोलियो असेट्स 70.33 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर आ गए हैं, जबकि 1 महीने पहले भारतीय शेयर बाजार में फॉरेन पोर्टफोलियो असेट्स 71.97 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर थे। यानी अगस्त के महीने में इसमें लगभग 2.30 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। एनएसडीएल के आंकड़ों के अनुसार अगस्त के महीने के अंत तक विदेशी निवेशकों के हिस्सेदारी भारतीय शेयर बाजार में घटकर 15.85 प्रतिशत रह गई है। विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी जहां लगातार घट रही है, वहीं भारतीय शेयर बाजार में घरेलू संस्थागत निवेश को हिस्सेदारी में लगातार वृद्धि हुई है।

लेज ने चमिट्टी की चिट्ठी' पहल के जरिए भारतीय किसानों को किया सम्मानित, स्पेशल पैक किए लॉन्च

नई दिल्ली। पेप्सिको इंडिया के पोटैटो चिप्स ब्रांड्स लेज ने भारतीय किसानों के चित्रों वाली एक सीमित-संस्करण पैक लॉन्च किए हैं। ये पैक आलू उगाने वालों और उन्हें खाने वालों के बीच के संबंध को उजागर करते हैं। सीमित समय के लिए चुनिंदा बाजारों में उपलब्ध ये लिमिटेड एडिशन क्लासिक साल्टेड पैक अब देशभर के रिटेल स्टोर्स और ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध होंगे। इसकी कीमत 50 रुपये है। लेज ने मिट्टी से मुस्कान तक की इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए पहली बार लिमिटेड एडिशन पैक पेश किया है। इस पैक में भारतीय किसानों को दर्शाया गया है। लेज ने अपने प्रतिष्ठित पैक को एक कहानी कहने वाले कैनवास में बदल दिया है, जिससे आलू उगाने वाले किसानों और उन्हें खाने वाले उपभोक्ताओं के बीच जुड़ाव और गहरा हो गया है। प्रत्येक पैक उपभोक्ताओं को उत्पाद का आनंद लेने के साथ-साथ खेत से लेकर पैक तक की यात्रा के बारे में जानने का अवसर देता है। लेज के इन पैक की खासियत हैं पुरुष और महिला किसानों के हाथ से बने चित्र, जिनके चारों ओर खेती और फसल कटाई के जीवंत दृश्य दर्शाए गए हैं, जो मिट्टी से स्नैक तक की यात्रा को जीवंत कर देते हैं। लेज का यह सीमित संस्करण वाले पैक उपभोक्ताओं के लिए मिट्टी की चिट्ठी लेकर आए हैं। लेज की एक फिल्म जो किसान और जमीन के बीच के रिश्ते को दर्शाती है।

रुपया नए निचले स्तर पर, डॉलर के मुकाबले 11 पैसे गिरकर 88.27 पर बंद हुई भारतीय मुद्रा

नई दिल्ली। विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली करने और भारत के आईटी सेक्टर पर अतिरिक्त अमेरिकी टैरिफ लगाए जाने की आशंका की वजह से भारतीय मुद्रा रुपये डॉलर की तुलना में अभी तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। भारतीय मुद्रा रुपये ने आज डॉलर की तुलना में 11 पैसे फिसल कर सबसे कमजोर क्लोजिंग का नया रिकॉर्ड बनाते हुए 88.27 (अनंतिम) के स्तर पर आज के कारोबार का अंत किया। रुपये ने आज के कारोबार की शुरुआत मजबूती के साथ ही की थी। इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भारतीय मुद्रा ने आज सुबह डॉलर के मुकाबले 16 पैसे की बढ़त के साथ 88.10 रुपये के स्तर से कारोबार की शुरुआत की थी। हालांकि आज का कारोबार शुरू होने के बाद रुपये पर लगातार दबाव बढ़ता गया, जिसकी वजह से रुपये की गिरावट बढ़ती चली गई। विदेशी निवेशकों द्वारा भारतीय बाजार से अपने पैसे की निकासी करने और अमेरिका द्वारा भारत के आईटी सेक्टर पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की अफवाह की वजह से मुद्रा बाजार में रुपये पर काफी दबाव बढ़ गया। इस अफवाह की वजह से रुपया डॉलर की तुलना में अभी तक सबसे निचले स्तर 88.38 तक गिर गया। हालांकि बाद में अतिरिक्त टैरिफ से जुड़ी खबरों का खंडन आने के बाद रुपये की स्थिति में कुछ सुधार हुआ।

चार्टर्ड स्पीड ने 855 करोड़ रुपये के आईपीओ के लिए दाखिल किया डीआरएचपी

नई दिल्ली। अहमदाबाद की चार्टर्ड स्पीड लिमिटेड कंपनी ने अपने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) दाखिल किया है। कंपनी की योजना इस इश्यू के जरिए 855 करोड़ रुपये जुटाने की है। शेयरों को एनएसई और बीएसई में सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है। पूंजी बाजार नियामक सेबी के समक्ष जमा दस्तावेज के मुताबिक पांच रुपये अंकित मूल्य वाले प्रस्तावित ये इश्यू 655 करोड़ रुपये तक के नए शेयरों का निर्गम और प्रमोटरों पंकज गांधी और अलका पंकज गांधी का क्रमशः 200 करोड़ रुपये तक के बिक्री प्रस्ताव है। इसमें पात्र कर्मचारियों का सदस्यता आरक्षण भी शामिल है, जबकि कर्मचारी आरक्षण वाले हिस्से में बोली लगाने वाले पात्र कर्मचारियों को छूट भी दी जा रही है। कंपनी 655 करोड़ रुपये के नए निर्गम से प्राप्त राशि का उपयोग 98 करोड़ रुपये मूल्य की इलेक्ट्रिक बसों में निवेश करेगी। इसके अलावा कंपनी 396.4 करोड़ रुपये का कुछ उधारों का पूर्व-भुगतान या पूर्ण या आंशिक पुनर्भुगतान और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए करेगी।

मध्य प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र में आया 32,500 करोड़ का निवेश, 17,000 लोगों को मिलेगा रोजगार

एजेंसी

भोपाल। मध्य प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र आया 32,500 करोड़ का निवेश आया है। यह प्रदेश सरकार की निवेश परक सार्थक प्रयासों और विकासउन्मुख नीतियों सकारात्मक परिणाम बताया जा रहा है। टोरेंट पॉवर और अडानी पॉवर जैसी बड़ी कंपनियों ने तो अब ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रदेश में काम करना भी शुरू कर दिया है। टोरेंट पॉवर कंपनी 22 हजार करोड़ और अडानी पॉवर कंपनी 10 हजार 500 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 17,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। जनसंपर्क अधिकारी क्रांतिदीप अलूने ने बताया कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निवेश संवर्धन प्रयासों के फलस्वरुप ऊर्जा क्षेत्र और ज्यादा मजबूत हो रहा है। ऊर्जा सुरक्षा बढ़ रही है। मध्य प्रदेश पॉवर सरप्लस राज्य के रूप में पहचान बना चुका है। ऊर्जा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के मुख्यमंत्री डॉ. यादव के प्रयासों से अब इस क्षेत्र में नया निवेश आ रहा है। उन्होंने बताया कि टोरेंट पॉवर 1600 मेगावॉट थर्मल प्रोजेक्ट के लिए प्रदेश में 22 हजार करोड़ रुपये का निवेश करेगी। टोरेंट पॉवर लिमिटेड को एमपी पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (एमपीपीएमसीएल) से 1,600 मेगावॉट के कोयला आधारित बिजली संयंत्र की स्थापना के लिए लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) दे दिया है। यह अहमदाबाद-स्थित समूह द्वारा बिजली क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। अलूने ने बताया कि यह परियोजना ग्रीनफील्ड 2×800 मेगावॉट की अल्ट्रा-सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित होगी और इसे डिजाइन, निर्माण, वित्तपोषण, स्वामित्व और संचालन (डीबीएफओओ) मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा।

टोरेंट इस संयंत्र की पूरी क्षमता एमपीपीएमसीएल को 25 साल की पॉवर परचेज एग्रीमेंट पॉवर परचेस एग्रीमेंट के तहत 5.829 रुपये प्रति यूनिट की दर से आपूर्ति करेगा। यह परियोजना पीपीए पर हस्ताक्षर होने के 72 महीनों के भीतर चालू होनी है। परियोजना लागत का लगभग 70फीसदी ऋण के माध्यम से पूरा किया जाएगा।

प्रधानमंत्री के स्वदेशी अभियान को नागपुर सम्मेलन में मिलेगी धारः प्रवीण खंडेलवाल

एजेंसी

नई दिल्ली। सांसद एवं कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का सपना अब तेजी से साकार हो रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की ओर से थोपा गया टैरिफ एक चुनौती नहीं, बल्कि अवसर है। खंडेलवाल ने यहां कांस्टीट्यूशन क्लब में कैट, स्वदेशी जागरण मंच, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, हॉकर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी एवं राष्ट्रीय उपभोक्ता मोर्चा द्वारा आयोजित संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि व्यापारी वर्ग यह प्रण लेता है कि हर दुकान, हर बाजार, हर रेहड़ी पर स्वदेशी वस्तुएं उपलब्ध कराई जाएंगी। विदेशी वस्तुओं का विकल्प केवल स्वदेशी ही होगा। अमेरिकी टैरिफ वॉर के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार-प्रसार एवं उपभोग को जन-आंदोलन बनाने के उद्देश्य से आयोजित इस प्रेस कांफ्रेंस में संयुक्त रूप से घोषणा की गई कि 15 और 16 सितंबर को नागपुर में ÷व्यापारी जुटान -राष्ट्रीय सम्मेलन' आयोजित होगा, जिसमें देशभर से 400 से अधिक व्यापारी नेताओं, हॉकर्स संगठनों, उपभोक्ता मंचों एवं उद्योग प्रतिनिधियों की मौजूदगी होगी। इस सम्मेलन के बाद राष्ट्रीय स्वदेशी अभियान पूरे देश के गांव-गांव, कस्बों और शहरों तक चलाया जाएगा। व्यापारी जुटान को लेकर आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया कि देशभर में 10 करोड़ से अधिक व्यापारी, रेहड़ी-पटरी वाले और छोटे रिटेल व्यवसायी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 82 लाख करोड़ रुपये के व्यापार से जुड़े हैं। आने वाले 10 वर्षों में यह आंकड़ा 190 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। लेकिन अमेजन और वालमार्ट जैसी बहुराष्ट्रीय ई-कॉमर्स कंपनियां अवैध माध्यम से बाजार में घुसपैठ कर रही हैं, जिससे छोटे व्यापारी गंभीर संकट में हैं।

जापान के इवाते प्रीफेक्चर के वाइस गवर्नर और जेआईसीए के प्रतिनिधिमंडल ने गुजरात के मुख्यमंत्री से की भेंट

एजेंसी

अहमदाबाद। जापान के इवाते प्रीफेक्चर के वाइस गवर्नर सासाकी जून के नेतृत्व में जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) के प्रतिनिधिमंडल ने गांधीनगर में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से भेंट की। राज्य सूचना विभाग ने अपने बयान में बताया कि यह प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली में आयोजित सेमीकॉन इंडिया 2025 में सहभागी होने के लिए भारत आया है। इस बीच प्रतिनिधिमंडल ने गुजरात में कार्यरत जापानी सेमीकॉन इंडस्ट्रीज की यात्रा की। यह प्रतिनिधिमंडल धोलेरा विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसआईआर) में कार्यरत सेमीकॉन उद्योगों की साइट भ्रमण करने के बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से मिला। उसने राज्य सरकार द्वारा जापानी उद्योगों को मिल रहे सहयोग पर आभार व्यक्त किया। राज्य में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज के तेजी से बढ़ रहे दायरे से भी यह प्रतिनिधिमंडल प्रभावित हुआ है।मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस बैठक-चर्चा के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत-जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों से राज्य में सेमीकंडक्टर सेक्टर में जापानी उद्योगों को अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। गुजरात चार सेमीकंडक्टर प्लांट वाला राज्य है और सेमीकंडक्टर हब बनने की प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहा है।इस संदर्भ में उन्होंने राज्य में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए जापान के इवाते प्रीफेक्चर के साथ टेक्निकल सपोर्ट तथा स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज, उच्च गुणवत्तायुक्त उत्पादों के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसे

क्षेत्रों में दीर्घकालीन परस्पर सहयोग की उत्सुकता व्यक्त की। इस बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव एम. के. दास, वित्त विभाग के प्रधान सचिव टी. नटराजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव पी. भारती तथा वरिष्ठ अधिकारी सहभागी हुए।

भारतीय कपड़ा उद्योग पर कितनी है संकट की घड़ी अमेरिकी टैरिफ का विकल्प हैं 40 नए बाजार

एजेंसी

नई दिल्ली। अमेरिका ने हाल ही में भारतीय कपड़ा और परिधान उत्पादों पर 50 प्रतिशत तक का भारी-भरकम टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। यह फैसला केवल एक व्यापारिक कदम नहीं है, बल्कि वैश्विक व्यापार समीकरणों में बदलते संतुलन का भी प्रतीक है। इस निर्णय ने भारतीय कपड़ा उद्योग को चिंता में डाल दिया है, क्योंकि अमेरिका भारत के लिए वर्षों से एक प्रमुख निर्यात बाजार रहा है। लेकिन हर संकट अपने भीतर अवसर भी छिपाए होता है। सवाल यह है कि क्या भारत इस चुनौती को अवसर में बदल पाएगा? क्या हमारे कपड़ा निर्यातक अमेरिकी बाजार पर निर्भरता घटाकर नए बाजारों में टिकाऊ पैठ बना सकेंगे? और क्या केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर इस विशाल उद्योग को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में और मजबूत बना पाएंगी?भारतीय कपड़ा उद्योग का अतीत इस संबंध में बताता है कि यह क्षेत्र कठिनाइयों से घबराकर पीछे हटने वाला नहीं है। कोविड-19 महामारी के दौरान जब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला चरमरा गई थी और लाखों श्रमिकों की रोजी-रोटी पर संकट मंडरा रहा था, तब भी यही उद्योग धीरे-धीरे उठ खड़ा हुआ और आज पहले से अधिक मजबूत दिखाई देता है। यही वजह है कि केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह का दावा है कि अमेरिकी टैरिफ से झटका जरूर लगेगा, लेकिन यह पूरे उद्योग को डिगा नहीं पाएगा। भारत का कुल कपड़ा और परिधान निर्यात लगभग 40 से 45 बिलियन डॉलर का है। इसमें अमेरिका की हिस्सेदारी केवल 8 से 10 प्रतिशत है। इस हिस्से में भी 50 से 60 प्रतिशत निर्यात सिर्फ 5 से 7 बड़े व्यापारी करते हैं। यानी अमेरिका पर निर्भरता इतनी व्यापक नहीं है जितनी दिखाई देती है। दरअसल, इसका अर्थ यह हुआ कि बड़े निर्यातक तो प्रभावित होंगे, लेकिन छोटे और मध्यम स्तर के व्यापारी तुलनात्मक रूप से कम संकट में रहेंगे। फिर भी यह कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिकी टैरिफ ने प्रतिस्पर्धा की चुनौती को और बढ़ा दिया है। अमेरिकी बाजार में बांग्लादेश, वियतनाम, मैक्सिको और तुर्की जैसे देशों की पकड़ पहले से ही मजबूत है। जब भारतीय उत्पादों पर 50 प्रतिशत तक अतिरिक्त शुल्क लगेगा, तो अमेरिकी खरीदार विकल्प तलाशने में देर नहीं करेंगे। ऐसे में भारत को अपनी रणनीति बदलनी ही होगी। यही वजह है कि सरकार ने इस चुनौती का जवाब बाजार विविधीकरण के रूप में दिया है। कपड़ा मंत्रालय ने 40 नए संभावित बाजारों की पहचान की है, जिनमें यूनाइटेड किंगडम, जापान, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात, रूस, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, नीदरलैंड्स, पोलैंड, कनाडा, मैक्सिको, बेल्जियम, तुर्की और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल हैं।

तूतुकोडी का वीओसी बंदरगाह बना देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन बनाने वाला बंदरगाह

एजेंसी

तूतुकोडी (तमिलनाडु)। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज यहां वी.ओ. चिदंबरनार बंदरगाह पर देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना शुरू की, जिससे यह बंदरगाह ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला बंदरगाह बन गया।इस मौके पर सोनोवाल ने 35.34 करोड़ रुपये की हरित मेथनॉल बंकरिंग सुविधा, 59.20 करोड़ रुपये का 6 मेगावाट पवन फार्म, 90 करोड़ रुपये का मल्टी-कार्गो बर्थ, 34.77 करोड़ रुपये की 4-लेन सड़क और 3 करोड़ रुपये का तमिलनाडु समुद्री विरासत संग्रहालय की नींव भी रखी। साथ ही, 1.46 करोड़ रुपये का 400 किलोवाट रूफटॉप सौर संयंत्र और 24.50 करोड़ रुपये का कोल जेटी-कन्वेयर सिस्टम भी शुरू किया। उन्होंने रेल कनेक्टिविटी के लिए आईपीआरसीएल और हरित मोबिलिटी के लिए एनटीपीसी के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए।

इसके तहत 3.87 करोड़ रुपये की हरित हाइड्रोजन परियोजना बंदरगाह की स्ट्रीट लाइटों और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए हाइड्रोजन बनाएगी, जो प्रधानमंत्री मोदी के नेट-जीरो मिशन को बढ़ावा देगी। हरित मेथनॉल परियोजना कांडला तूतीकोरिन हरित शिपिंग कॉरिडोर में सहयोगी साबित होगी। इस सौर संयंत्र से बंदरगाह की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता 1.04 मेगावाट हो गई, जो देश के बंदरगाहों में सबसे ज्यादा है। ये परियोजनाएं तमिलनाडु में हजारों नौकरियां पैदा करेंगी, व्यापार बढ़ाएंगी और 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में योगदान देंगी। सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत का समुद्री क्षेत्र अभूतपूर्व प्रगति कर रहा है। साल 2047 तक विकसित भारत की उनकी अपील /आह्वान गति, पैमाने, स्थिरता और आत्मनिर्भरता का मिश्रण है। तमिलनाडु में शुरू की जा रही परियोजनाएं हजारों रोजगार सृजित करेंगी, व्यापार को बढ़ावा देंगी और वैश्विक निवेश आकर्षित करेंगी। इससे तमिलनाडु 2027 तक भारत की 5 ट्रिलियन डॉलर और 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में योगदान देगा। वीओसी बंदरगाह नवीकरणीय ऊर्जा और हरित बंकरिंग के साथ भारत का हरित हाइड्रोजन और अमोनिया केंद्र बनेगा।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ दो दिवसीय 'पीएसबी मंथन' करेगा वित्त मंत्रालय

एजेंसी

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के शीर्ष नेतृत्व के साथ अगली पीढ़ी के बैंकिंग सुधारों पर दो दिवसीय 'पीएसबी मंथन' करेगा। 12 सितंबर से शुरू होने वाले 'पीएसबी मंथन' में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के शीर्ष प्रबंधन के लोग भाग लेंगे। इसका मकसद देश में बैंकिंग गतिविधियों को आसान बनाना है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पीएसबी के शीर्ष नेतृत्व के साथ अगली पीढ़ी के सुधारों को गति देने के लिए बैंकों के साथ इस तरह का पिछला मंथन अप्रैल, 2022 में आयोजित किया गया था। तब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संपूर्ण नेतृत्व ने वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) की देखरेख में उन्नत पहुंच और सेवा उत्कृष्टता (ईज) सुधारों को अगले स्तर तक ले जाने पर चर्चा की गई थी। च्ईज' नवंबर 2017 में आयोजित च्पीएसबी मंथन' की सिफारिशों पर आधारित है। पिछले मंथन में पीएसबी के कामकाज की समीक्षा करने और ग्राहक सेवा, डिजिटलीकरण, मानव संसाधन प्रोत्साहन, कॉरपोरेट प्रशासन

और सहयोग में सुधार के उपाय सुझाने के लिए छह कार्य समूहों का गठन किया गया था। पीएसबी मंथन का नया दौर पीएसयू बैंकों के संचयी लाभ के 31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष 2024-25 में 1.78 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचने की पृष्ठभूमि में आयोजित होगा, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 26 फीसदी की वृद्धि है।

रेनॉल्ट भी कार की कीमतों में करेगी 96,395 रुपये की कटौती, नई दरें 22 सितंबर से होंगी लागू

एजेंसी

नई दिल्ली। टाटा मोटर्स के बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा और रेनॉल्ट इंडिया ने शनिवार को अपनी कारों की कीमतों में 96,395 रुपये तक की कटौती का ऐलान किया है। नई कीमतें नवरात्रि के पहले दिन 22 सितंबर से शुरू होने वाली सभी कारों की डिलीवरी पर लागू होंगी। हालांकि, देशभर के डीलरशिप पर संशोधित कीमतों पर बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है। रेनॉल्ट इंडिया ने शनिवार को जारी बयान में बताया कि वह अपनी कारों की कीमतों में 96,395 रुपये तक की कटौती करेगी, जिससे हाल ही में जीएसटी की दरों में की गई कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों को मिलेगा। कंपनी ने कहा कि नई कीमतें नवरात्रि के पहले दिन 22 सितंबर, 2025 से शुरू होने वाली सभी डिलीवरी पर लागू होंगी। रेनॉल्ट इंडिया के एमडी वेंकटराम मामिलपल्ले ने जारी बयान में कहा, जीएसटी 2.0 का पूरा लाभ ग्राहकों तक पहुंचाना ग्राहकों के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हमारा मानना है कि यह समय पर की गई पहल न केवल हमारी

कारों को और अधिक सुलभ बनाएगी, बल्कि त्योहारी सीज़न के दौरान मांग को भी बढ़ावा देगी। नई जीएसटी व्यवस्था के तहत छोटी कारों पर 18 फीसदी, जबकि बड़ी कारों पर 40 फीसदी जीएसटी लगेगा। कंपनी के नवीनतम संशोधनों के साथ रेनॉल्ट इंडिया के मॉडल अब पहले से कहीं अधिक सुलभ हैं। एंट्री-लेवल पर रेनॉल्ट क्विड की शुरुआती कीमत अब केवल 4.29 लाख रुपये है, जबकि रेनॉल्ट काइगर और रेनॉल्ट ट्राइबर की शुरुआती कीमत 5.76 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) है। वेरिएंट के आधार पर कीमतों में 40,095 रुपये से लेकर 96,395 रुपये तक की कटौती की गई है। 22 सितंबर से नई कर दरें लागू होने के साथ ऑटो कंपनियां ग्राहकों को जीएसटी का लाभ देने की तैयारी कर रही हैं। इसी के तहत टाटा मोटर्स ने शुक्रवार देर रात अपनी कारों की कीमतों में 1.40 लाख रुपये की कटौती की घोषणा की थी। वहीं, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने आज कहा कि वह कीमत में 1.56 लाख रुपये तक की कटौती करेगी और इसका पूरा लाभ ग्राहकों को देगी। वहीं, मारुति सुजुकी इंडिया से भी जल्द ही कीमतों में कटौती की घोषणा करने की उम्मीद है।

टाटा मोटर्स के यात्री वाहन 22 सितंबर से 1.45 लाख रुपये तक होंगे सस्ते

एजेंसी

नई दिल्ली। वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर में हुई कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों को देने के इरादे से अपने यात्री वाहनों की कीमतों में 65 हजार रुपये से 1.45 लाख रुपये तक की कटौती करने का ऐलान किया है। नई दरें 22 सितंबर से प्रभावी हो जाएगी। टाटा मोटर्स ने जारी बयान में कहा कि कंपनी ने अपने यात्री वाहनों के लिए कर की दरों में कटौती करने का फैसला जीएसटी परिषद के बुधवार को लिए गए फैसले के अनुरूप लिया है। कंपनी ने कहा कि यात्री वाहनों की कीमतों में यह कटौती नवरात्रि के पहले दिन 22 सितंबर से प्रभावी हो जाएगी। मुंबई स्थित कंपनी ने कहा कि टाटा मोटर्स की छोटी कार टियागो अब 75,000 रुपये सस्ती हो जाएगी, जबकि टिगोर के दाम में 80 हजार रुपये और अल्ट्रोज की कीमत में 1.10 लाख रुपये की कटौती होने जा रही है। इसी तरह कॉम्पैक्ट एसयूवी च्पंच' की कीमत 85,000 रुपये और नेक्सॉन के दाम 1.55 लाख रुपये तक घट जाएंगे। कंपनी ने बताया कि मिड-साइज मॉडल च्कर्व' की कीमत में 65,000 रुपये की कमी होगी। वहीं, प्रीमियम एसयूवी मॉडल च्हैरियर' और च्सफारी' की कीमतों में क्रमशः 1.4 लाख रुपये और 1.45 लाख रुपये तक की कटौती की जाएगी। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के प्रबंध निदेशक (एमडी) शैलेश चंद्रा ने कहा, च्प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण, वित्त मंत्री की मंशा और हमारी च्ग्राहक प्रथम' नीति के अनुरूप टाटा मोटर्स इस कर सुधार का पूरा लाभ ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।'' चंद्रा ने कहा कि जीएसटी कटौती से टाटा मोटर्स की लोकप्रिय कारें और एसयूवी ज्यादा ग्राहकों की पहुंच में आएंगी, जिससे पहली बार वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को मदद मिलेगी और नए युग के परिवहन की तरफ बदलाव को गति मिलेगी। उल्लेखनीय है कि जीएसटी की नई कर के तहत अब 1,200 सीसी तक के पेट्रोल, एलपीजी एवं सीएनजी वाहन और 1500 सीसी तक के डीजल वाहन (लंबाई 4,000 मिमी से कम) 18 फीसदी की दर में आएंगे।

देश का विदेशी मुद्रा भंडार 3.51 अरब डॉलर बढ़कर 694.23 अरब डॉलर पर

नई दिल्ली। देश का विदेश मुद्रा भंडार 29 अगस्त को समाप्त हफ्ते में 3.51 अरब डॉलर बढ़कर 694.23 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। इससे पिछले हफ्ते में कुल विदेशी मुद्रा भंडार 4.39 अरब डॉलर घटकर 690.72 अरब डॉलर रह गया था। रिजर्व बैंक

ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने जारी आंकड़ों में बताया कि 29 अगस्त को समाप्त हफ्ते में विदेशी मुद्रा भंडार का प्रमुख घटक, विदेशी मुद्रा आस्तियां 1.69 अरब डॉलर बढ़कर 583.94 अरब डॉलर हो गई। इस दौरान स्वर्ण भंडार का मूल्य 1.77 अरब डॉलर बढ़कर 86.77 अरब डॉलर पर पहुंच गया। आंकड़ों के मुताबिक कि इस दौरान विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) चार करोड़ डॉलर बढ़कर 18.77 अरब डॉलर हो गया। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के पास भारत का आरक्षित भंडार भी 1.8 करोड़ डॉलर बढ़कर 4.75 अरब डॉलर पर पहुंच गया। देश का विदेशी मुद्रा भंडार इससे पहले सितंबर, 2024 के अंत में बढ़कर 704.88 अरब डॉलर के अबतक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था।

दिनभर उतार-चढ़ाव के बाद सपाट स्तर पर बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स ऊपरी स्तर से 715 अंक लुढ़का

एजेंसी

नई दिल्ली। घरेलू शेयर बाजार आज पूरे दिन उतार-चढ़ाव का सामना करने के बाद सपाट स्तर पर मिले-जुले परिणाम के साथ बंद हुआ। आज के कारोबार की शुरुआत मजबूती के साथ हुई थी। बाजार खुलते ही खरीदारी के सपोर्ट से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों सूचकांकों की चाल में मामूली तेजी भी आई। इसके बाद बिकवाली का दबाव बन जाने की वजह से दोनों सूचकांक अपनी सारी बढ़त गंवा कर लाल निशान में गिर गए। हालांकि दिन के दूसरे सत्र में एक बार फिर खरीदारों ने मोर्चा संभाला, जिसकी वजह से शेयर बाजार निचले स्तर से रिकवरी करने में सफल रहा। पूरे दिन के कारोबार के बाद सेंसेक्स 0.009 प्रतिशत की कमजोरी के साथ और निफ्टी 0.027 प्रतिशत की मामूली बढ़त के साथ बंद होने में सफल रहे। आज दिनभर के कारोबार के दौरान ऑटोमोबाइल और मेटल सेक्टर के शेयरों में जमकर खरीदारी होती रही। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, हेल्थ केयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल और बैंकिंग इंडेक्स भी मामूली तेजी के साथ बंद होने में सफल रहे। दूसरी ओर, आईटी, एफएमसीजी और टेक सेक्टर के शेयरों में आज लगातार बिकवाली का दबाव बना रहा। इसी तरह ऑयल एंड गैस और कैपिटल गुड्स इंडेक्स भी कमजोरी के साथ बंद हुए। ब्रॉडर मार्केट में आज मिला-जुला कारोबार होता रहा, जिसके कारण बीएसई का मिडकैप इंडेक्स 0.10 प्रतिशत की कमजोरी के साथ बंद हुआ। वहीं, स्मॉलकैप इंडेक्स ने 0.09 प्रतिशत की बढ़त के साथ आज के कारोबार का अंत किया। आज शेयर बाजार में लगातार उतार-चढ़ाव होने और सपाट स्तर पर बंद होने के बावजूद स्टॉक मार्केट के निवेशकों की संपत्ति में करीब 16 हजार करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हो गई। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन आज के कारोबार के बाद बढ़ कर 451.44 लाख करोड़ रुपये (अनंतिम) हो गया। जबकि पिछले कारोबारी दिन यानी गुरुवार को इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 451.28 लाख करोड़ रुपये था। इस तरह निवेशकों को आज के कारोबार से करीब 16 हजार करोड़ रुपये का मुनाफा हो गया। आज दिनभर के कारोबार में बीएसई में 4,260 शेयरों में एक्टिव ट्रेडिंग हुई। इनमें 2,134 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि 1,957 शेयरों में गिरावट का रुख रहा, वहीं 169 शेयर बिना किसी उतार-चढ़ाव के बंद हुए। एनएसई में आज 2,776 शेयरों में एक्टिव ट्रेडिंग हुई। इनमें से 1,411 शेयर मुनाफा कमा कर हरे निशान में और 1,365 शेयर नुकसान उठा कर लाल निशान में बंद हुए। इसी तरह सेंसेक्स में शामिल 30 शेयरों में से 14 शेयर बढ़त के साथ और 16 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। जबकि निफ्टी में शामिल 50 शेयरों में से 27 शेयर हरे निशान में और 23 शेयर लाल निशान में बंद हुए। बीएसई का सेंसेक्स आज 294.41 अंक उछल कर 81,012.42 अंक के स्तर पर खुला। कारोबार की शुरुआत होते ही ये सूचकांक खरीदारी के सपोर्ट से 318.55 अंक की बढ़त के साथ 81,036.56 अंक तक पहुंच गया। इस उछाल के तुरंत बाद बिकवाली का दबाव बन गया, जिसकी वजह से इस सूचकांक की चाल में गिरावट आ गई। लगातार हो रही बिकवाली के कारण सेंसेक्स ऊपरी स्तर से 715.37 अंक टूट कर 396.82 अंक की कमजोरी के साथ 80,321.19 अंक तक गिर गया। हालांकि दोपहर एक बजे के थोड़ी देर पहले खरीदारों ने एक बार फिर मोर्चा संभाला, जिसकी वजह से इस सूचकांक की चाल में सुधार होने लगा। लगातार हो रही खरीदारी के सपोर्ट से सेंसेक्स निचले स्तर से करीब 390 अंक की रिकवरी करके 7.25 अंक की मामूली गिरावट के साथ 80,710.76 अंक के स्तर पर बंद हुआ।

बेटियां बिना बिजली और पानी....हिमाचल में फंसी

रूबीना दिलैक

की जुड़वा बेटियां,तड़प रहा मां का दिल

भारी बारिश और बाढ़ के कारण भारत के कई राज्यों में हालात बेहद खराब हैं। देश के कई शहरों में जलजमाव, सड़कों पर पीनी भर गया है। जिसके कारण जन जीवन पूरी तरीके से प्रभावित है।हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हो रही लगातार बारिश के कारण हालात बेहद खराब हो चले हैं। भूस्खलन और पेड़ों के गिरने के कारण बुधवार तक राज्य में विद्यालयों को बंद रखा गया। हाल ही में रूबीना दिलाइक ने हिमाचल प्रदेश में चल रहे संकट के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि इस बुरे दौर में उनकी बेटियां भी वहीं हैं।

रूबीना ने वीडियो में कहा, बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि आप हिमाचल के बारे में कुछ पोस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, कितनी तबाही हो रही है वहां पर, बारिश की वजह से, इतने सारे भूस्खलन, पेड़ गिर रहे हैं, कनेक्शन पूरी तरह से जा चुका है, सड़कें बह रही हैं।

वह रुकीं और बोलीं, मेरे पास सच में कहने के लिए कुछ नहीं है। कुदरत के आगे कोई कुछ नहीं कर पाएगा। पिछले 4 दिनों से मेरा खुद का परिवार हमारे फार्म हाउस पर मेरी बेटियां हैं, मेरे माता-पिता हैं, मेरी दादी हैं। उनके पास पिछले 3 दिनों से बिजली नहीं है, सेल्युलर नेटवर्क नहीं है, पानी का सोर्स जो है वो बाढ़ है। हम सुरक्षित हैं पर जिस तरह से सब लोग गुजर रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ हम प्रार्थना कर सकते हैं।

रूबीना दिलाइक ने आगे कहा- यहां घर बैठे-बैठे हमें चिंता रहती है। पिछले 2 हफ्ते से मैं और अभिनव अपनी फ्लाइट शेड्यूल कर रहे हैं पर हमें मौका ही नहीं मिल रहा। कभी भूस्खलन हो रहा है। मैं जो 15 दिन पहले गई थी तभी भूस्खलन की स्थिति खत्म हो गई थी। तो मैं समझ सकती हूं हिमाचल में, असल में पंजाब में जो अभी स्थिति है उसमें बहुत सारे लोग बहुत सी दिक्कतों के साथ जी रहे हैं और हम, मैं खास करके भगवान से सिर्फ इतनी ही प्रार्थना कर सकते हैं कि हम सभी को सुरक्षित रखें।

अंत में रूबीना ने कहा, अभी सिर्फ सभी के लिए यही मेरी प्रार्थना है और सोशल मीडिया के जरिए अगर कोई फंड जुटाए या फिर किसी की मदद की जरूरत है वो मैं जरूर कर सकती हूं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपसे मैं शेयर करना चाहती हूं और मेरा परिवार भी इस स्थिति से जी रहा है और मैं बस भगवान से प्रार्थना कर रही हूं कि हम सभी इस प्राकृतिक आपदा से मजबूत होकर बाहर आएं और सभी सुरक्षित रहें। मैं सभी प्रभावित परिवारों के लिए अपनी प्रार्थनाएं और प्यार भेज रही हूं।

जिसने संवारा Bobby Deol का करियर अब उसके हाथ में 18 फ्लॉप देने वाले एक्टर का फ्यूचर, क्या जमेगी जोड़ी?

बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कई सारे स्टारकिड्स ने अपना करियर बनाया है. कुछ का करियर शुरुआत में चला बाद में ठप्प हो गया तो कुछ कलाकार ऐसे भी थे जिनका करियर शुरू में उतना सही नहीं रहा लेकिन बाद में चला. इसके बावजूद भी कुछ स्टार किड्स ऐसे हैं जो अभी तक अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे हैं. इसमें एक नाम तुषार कपूर का लिया जा सकता है. उन्होंने भले ही अपने करियर की शुरुआत एक हिट फिल्म से की थी लेकिन इसके बाद उनके करियर में कई सारी फ्लॉप फिल्में आईं. भले ही गोलमाल सीरीज से उन्हें थोड़ी राहत मिली लेकिन इसके बाद फिर से एक्टर का करियर डगमगाता नजर आ रहा है. लेकिन अब उनकी नैया पार लगाने के लिए उस डायरेक्टर ने हाथ मिला लिया है जिसने कुछ साल पहले बॉबी देओल के साथ कोलाबोरेट किया था और एक्टर की गाड़ी पटरी पर ला दी थी.

तुषार कपूर-प्रकाश झा ने मिलाया हाथ

तुषार कपूर ने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट की खुद अनाउंसमेंट करते हुए कहा- प्रकाश जी ने मुझे कॉल की और बताया कि उनके पास मेरे लिए इस फिल्म में एक कैरेक्टर है. उनके मुताबिक ये कैरेक्टर अचानक ही निकलकर बाहर आ गया. जैसे की ये ब्रह्मांडा का ही कोई संकेत हो. ये फिल्म मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि दर्शकों के बीच में बनी मेरी किसी किरदार की छवि को मुझे तोड़ना है. मैं दरअसल प्रकाश झा जैसे ही किसी डायरेक्टर के साथ पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म की तलाश कर रहा था. क्योंकि वो इस जॉनर के एक्स्पर्ट हैं. मैं उनके काम की बहुत प्रशंसा करता हूं और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे इस अवसर को एक्स्प्लोर करने का मौका मिला है.

रोल की तैयारी कैसे कर रहे तुषार कपूर ?

एक्टर तुषार कपूर की बात करें तो एक्टर मौजूदा समय में इस फिल्म को लेकर बिजी हैं और वे प्रकाश झा के साथ मिनी-वर्कशॉप्स की तैयारी कर रहे हैं जिससे वे कैरेक्टर को समझ सकें और उसके अंदर घुस सकें. साथ ही तुषार ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर प्रकाश उन्हें इस रोल में किस तरह से देखना चाहते है. तुषार ने अपने किरदार के बारे में ये भी बताया कि ये किसी रियल लाइफ पर्सनालिटी पर बेस्ड कैरेक्टर नहीं है और ये पूरी तरह से एक फिक्शनल कैरेक्टर है.

करिश्मा कपूर या करीना कपूर खान, दोनों बहनों में से किसके पास है ज्यादा पैसा?

बॉलीवुड में कपूर सिस्टर्स करीना कपूर खान और करिश्मा कपूर दोनों ने ही बड़ा और खास नाम कमाया है. करिश्मा जहां अपने दौर की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक रहीं. तो वहीं करीना ने भी अपनी बेहतरीन अदाकारी से ऐसा ही जादू चलाया है. दोनों ने खूब नाम कमाने के साथ ही खूब दौलत भी कमाई है. तो चलिए आज जानते हैं कि आखिर दोनों बहनों में से कौन ज्यादा रईस हैं ?करिश्मा कपूर ने महज 16 साल की उम्र में बॉलीवुड में अपना करियर शुरू कर दिया था. उनकी पहली फिल्म साल 1991 में रिलीज हुई थी और वो 90 के दशक की टॉप एक्ट्रेस रहीं. वहीं करीना के करियर की शुरुआत 2000 में हुई थी. उन्होंने भी एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया और आज भी करीना बॉलीवुड में एक्टिव हैं.

करिश्मा कपूर की नेटवर्थ

अभिनेता रणधीर कपूर और अभिनेत्री बबीता की बड़ी बेटी करिश्मा कपूर का जन्म 25 जून 1974 क हुआ था. शुरू से ही उन्हें घर में फिल्मी माहौल मिला था और वो महज 16 साल की उम्र में एक्ट्रेस बन गई थीं. अपने करियर में करिश्मा ने 'राजा हिंदुस्तानी', 'हीरो नंबर 1', 'साजन चले ससुराल', 'दिल तो पागल है', 'जीत', 'राजा बाबू', 'कुली नंबर 1' और 'हम साथ साथ हैं' जैसी कई बेहतरीन फिल्में दी हैं. वहीं करिश्मा की नेटवर्थ की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्ट्रेस 120 करोड़ रुपये की नेटवर्थ की मालकिन हैं.

करीना कपूर की नेटवर्थ

करीना कपूर खान ने भी अपने पैरेंट्स और बड़ी बहन करिश्मा की राह पर चलते हुए बॉलीवुड में ही अपना करियर बनाया. करीना का जन्म सितंबर 1980 में हुआ था और वो 20 साल की उम्र में एक्ट्रेस बन गई थीं.

फिल्म 'रिफ्यूजी' से अपने कदम हिंदी सिनेमा में रखने वाली करीना ने अपने करियर में 'कभी खुशी कभी गम', 'क्रू', 'वीरे दी वेडिंग', 'जब वी मेट', 'थ्री इडियट्स', 'बॉडीगार्ड', 'गुड न्यूज', 'ऐतराज', 'तलाश', और 'बजरंगी भाईजान' जैसी शानदार फिमों में काम किया है.

करीना अपने 25 साल के करियर में खूब शोहरत के साथ ही खूब दौलत भी कमा चुकी हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीना की नेटवर्थ 485 करोड़ रुपये है जो करिश्मा की नेटवर्थ से बहुत ज्यादा है.

'लव एंड वॉर' की शूटिंग के दौरान

आलिया भट्ट

के सामने थी बड़ी चुनौती! बेटी राहा की खातिर चुना ये रास्ता

आलिया भट्ट, संजय लीला भंसाली की मच अवेटेड फिल्म लव एंड वॉर में अपने पति और एक्टर रणबीर कपूर के साथ दूसरी बार स्क्रीन शेयर करने के लिए तैयार हैं. विकी कौशल भी इस फिल्म के लीड हीरो हैं. हाल ही में आलिया ने अपनी निजी और प्रोफेशनल ज़िंदगी, खासकर अपनी बेटी राहा की मां होने के नाते, के बीच बैलेंस बनाने के बारे में खुलकर बात की. आलिया ने बताया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी और उन्होंने इसे कैसे मैनेज किया.आलिया और रणबीर बीते कई महीनों से भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर पर काम कर रहे हैं. फिल्म की शूटिंग का बड़ा हिस्सा मुंबई में ही शूट किया गया है. लेकिन अब फिल्म क्लाइमेक्स शूट करने के लिए विदेश रवाना होने वाली है. ऐसे में आलिया ने रणबीर के साथ काम करना, राहा की परवरिश और वर्क लाइफ के बीच तालमेल बैठाने को लेकर चर्चा की.

रात में शूट की लव एंड वॉर - आलिया

आलिया ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसके कोई नुकसान नहीं हैं, बल्कि फायदे ही फायदे हैं. बस एक ही चुनौती है, शायद राहा का शेड्यूल और समय मैनेजमेंट. हमने ज़्यादातर फिल्म रात में ही बनाई है, इसलिए ज़्यादातर हम दिन में उनके साथ ही रहेंगे. कुछ दिन ऐसे होते हैं जब वह शूटिंग करते हैं, कुछ दिन मैं शूटिंग करती हूं और हम हमेशा एक ही समय पर शूटिंग नहीं कर पाते. इसी बातचीत में आलिया ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अपनी बेटी के लिए मौजूद रहते हुए, काम और ज़िंदगी के बीच एक हेल्दी बैलेंस बनाए रखना उनकी प्रायोरिटी है, जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता.

बेटी की वजह से ठुकराई कई फिल्में

आलिया ने आगे बताया, इसका मतलब है कि आप जरूरत से ज़्यादा जिम्मेदारी न लें और ऐसे लोगों के साथ काम करें जो आपकी प्रायोरिटी और बैलेंस की ज़रूरत को समझते हों. यह बैलेंस पाना अब नेचुरल हो गया है. हर महीने, जब मैं अपना शेड्यूल मैनेज करती हूं, तो उसे क्लियर रखती हूं कुछ भी अस्पष्ट नहीं होता. मुझे यह बहुत पसंद है, मैं कई ग्रुप्स में होती हूं और कुछ-कुछ प्लान करती हूं. हो सकता है कि मेरी कहानी मेरे बगल में बैठी मां जैसी न हो, लेकिन हमारा इरादा एक ही है. वर्किंग प्रोफेशनल होने के साथ-साथ एक ही समय पर माता-पिता भी होना और दोनों का थोड़ा-थोड़ा होना -हर जगह मौजूद रहना, हाथ बंटाना, पालन-पोषण करना, आगे बढ़ना.

'समर्थ उत्तर प्रदेश-2047' अभियान: 8-9 सितम्बर को बरेली में कार्यशाला

बरेली। समर्थ उत्तर प्रदेश-विकसित उत्तर प्रदेश/2047 अभियान को जन-जन तक पहुँचाने के लिए जिले में कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने कैम्प कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर इसकी रूपरेखा तय की। उन्होंने कहा कि 08 व 09 सितम्बर को विभिन्न लक्षित समूहों–छात्र, शिक्षक, उद्यमी, कृषक, व्यापारी, स्वयंसेवी संगठन, श्रमिक संगठन, मीडिया और आमजन को विगत आठ वर्षों की प्रदेश की विकास यात्रा

फोटोः शिव ठाकुर

से अवगत कराया जाएगा। साथ ही, राज्य के भविष्य के रोडमैप पर चर्चा कर सुझाव लिए जाएंगे। डीएम ने बताया कि कार्यशाला में वर्ष 2047 तक यूपी को विकसित राज्य बनाने के लिए तैयार विजन डॉक्यूमेंट साझा किया जाएगा। इसमें तीन मिशन–समग्र विकास, आर्थिक नेतृत्व और सांस्कृतिक पुनर्जागरण शामिल हैं। समग्र विकास के तहत हर नागरिक को बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर ढंग से उपलब्ध कराना है। आर्थिक नेतृत्व मिशन में उद्योग, कृषि और सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देकर यूपी को राष्ट्रीय व वैश्विक स्तर पर आर्थिक शक्ति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सांस्कृतिक पुनर्जागरण के तहत परंपरा और आधुनिक तकनीक के मेल से सामाजिक-सांस्कृतिक उत्थान किया जाएगा।

विजन डॉक्यूमेंट में तीन थीम–अर्थशक्ति, सृजनशक्ति और जीवनशक्ति तथा 12 प्रमुख सेक्टरों जैसे कृषि, पशुधन संरक्षण, औद्योगिक विकास, आईटी व इमेजिंग, पर्यटन, नगर व ग्राम्य विकास, अवस्थापना, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा-सुशासन पर फोकस किया गया है।

डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विषयवार कार्यशालाओं का आयोजन कर अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए और ग्राम पंचायत स्तर तक गोष्ठियों का आयोजन कर जनता से फीडबैक लिया जाए। बैठक में उद्योग, कृषि, शिक्षा, श्रम, कारखाना, प्रोबेशन व सूचना विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में एक भव्य फोटो एग्ज़िबिशन एवं प्रतियोगिता का आयोजन किया गया

दिव्य दिल्ली : मीडिया फोटो जर्नलिस्ट ट्रस्ट (Welfare Association of Press Photographer) द्वारा प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में एक भव्य फोटो एग्ज़िबिशन एवं प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ निगम पार्षद (मनोनीत) श्री मनोज कुमार जैन ने किया। इस अवसर पर श्री जैन ने फोटोग्राफर्स की कला और समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि प्रतिभाशाली फोटोग्राफर्स न केवल पत्रकारिता को सशक्त बना रहे हैं, बल्कि समाज में जागरूकता और संवेदनशीलता भी फैला रहे हैं। आयोजन में अध्यक्ष नवल हंस, महासचिव कमर सिब्तैन, उपाध्यक्ष विजय वर्मा, कोषाध्यक्ष वसीम सरवर सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। शैलेश गिरी की उपस्थिति ने कार्यक्रम की गरिमा को और बढ़ाया। प्रदर्शित चित्रों ने मीडिया कर्मियों की रचनात्मकता और समाज के प्रति जिम्मेदारी को उजागर किया। श्री मनोज कुमार जैन ने अंत में आयोजकों का आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में ऐसे सार्थक आयोजनों के निरंतर आयोजन की शुभकामनाएँ दीं।

प्राची की मौत के दोषियों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज नहीं हुई, तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगीं: साक्षी

मृतका की बड़ी बहन साक्षी मिश्रा परिवार के सदस्यों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की

शिवानी ठाकुर

जौनपुर। नगर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत 25 अगस्त सोमवार को मछलीशहर पड़ाव पर बारिश के दौरान खुले नाले और करंट की चपेट में आकर 24 वर्षीय प्राची मिश्रा की मौत के बाद परिजनों का दर्द और गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। मृतका की बड़ी बहन साक्षी मिश्रा परिवार के सदस्यों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। लेकिन एसपी की अनुपस्थिति में मौजूद सीओ सिटी देवेश कुमार सिंह ने मामले की जांच लम्बित होने का हवाला देते हुए एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया। सीओ सिटी के इस जवाब पर साक्षी मिश्रा भड़क उठीं। उन्होंने तर्क दिया कि "यदि अभी तक जांच पूरी नहीं हुई, तो आखिरकार नगर पालिका परिषद के दो कर्मचारियों और दो जूनियर इंजीनियर को किस आधार पर निलम्बित किया गया? जब निलम्बन हो सकता है, तो एफआईआर क्यों नहीं?" साक्षी ने मीडिया से बातचीत में साफ कहा कि यह जिला प्रशासन की दोहरी नीति है। एक तरफ प्रशासन सिर्फ दिखावे के लिए कुछ कर्मचारियों को

सस्पेंड कर देता है, वहीं दूसरी तरफ दोषी अधिकारियों और जिम्मेदार विभागों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने से बच रहा है।

साक्षी मिश्रा ने कहा कि उनकी बहन प्राची जीवन से भरपूर, सकारात्मक और भविष्य के सपनों से भरी हुई युवती थी। लेकिन नगर पालिका की खुली नालियां, पीडब्ल्यूडी की टूटी-फूटी सड़कें और बिजली विभाग के लटकते तारों ने उसकी जिंदगी छीन ली। उन्होंने आरोप लगाया कि "यह किसी सामान्य हादसे की मौत नहीं है, बल्कि विभागीय अधिकारियों की गंभीर लापरवाही और पदेन कर्तव्यों की उपेक्षा है।

इन्हें पूरी जानकारी थी कि इस तरह की स्थितियां किसी भी क्षण मौत का कारण बन सकती हैं, फिर भी सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए।"साक्षी ने जिला प्रशासन को सीधे कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को बचाने के लिए केवल निलम्बन की औपचारिकता पूरी की जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया झ "जब तक किसी विभागीय अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होगी और गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक यह न्याय अधूरा रहेगा। तीन निर्दोष लोगों की मौत के बाद भी यदि सिर्फ फाइलों में कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी, तो यह शासन की संवेदनहीनता और लापरवाही को उजागर करता है।" साक्षी मिश्रा ने कहा कि यदि उनकी बहन प्राची की मौत के दोषियों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज नहीं हुई, तो वे न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी।

आगरा में 6 सितंबर को सजेगा बागेश्वर धाम महाराज का दरबार

अजीज सैफी

आगराः उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद में 6 सितंबर को बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री आशीर्वचन कार्यक्रम के माध्यम से लोगों से रूबरू होकर आशीष देंगे। आगरा के तार घर मैदान में इस बड़े कार्यक्रम की तैयारी चल रही हैं। महाराज की आगमन को लेकर जगह होर्डिंग्स लगाये गये हैं। कार्यक्रम के लिए तोर घर मैदान में भूमि पूजन बुधवार को किया गया। 6 सितंबर को मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम पीठ के मठाधीश धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का आगरा में पहली बार आशीर्वचन और सत्संग कार्यक्रम सदर बाजार क्षेत्र के अंतर्गत तारघर मैदान में आयोजित किया जाएगा। उनके आगरा आगमन को लेकर अनुयायियों और श्रद्धालुओं में एक उत्साह और खुशी की लहर है। इस कार्यक्रम में लगभग 30 से 40 हजार लोगों के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। आगरा में बागेश्वर धाम महाराज का प्रथम कार्यक्रम होने के कारण लोगों में जिज्ञासा है। कार्यक्रम के आयोजक पुष्कल गुप्ता ने बताया कि महाराज जी का कार्यक्रम एक दिवसीय और कुछ घंटे का ही है फिर भी हम लोग कार्यक्रम में अनुमान से अधिक भीड़ की संभावना को देखते हुए और बरसात का मौसम होने के कारण जर्मन हैंगर की व्यवस्था कर रहे हैं जिससे श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो। स्थानीय पुलिस भी हाथरस में भोले बाबा के कार्यक्रम के दौरान मची भगदड़ को ध्यान में रखते हुए भीड़ नियंत्रण के लिए सभी कारगर उपाय अपनाने की तैयारी में है। बताते चलें कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बागेश्वर धाम नमक धार्मिक स्थल के पीठाधीश हैं हर एक मंगल और शनिवार को बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचकर उनके दर्शन और सत्संग के लिएके लिए आतुर रहते हैं।

अलीगढ़ में हुआ इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड सीजन 8 का भव्य आयोजन

अलीगढ़। द न्यू प्रिंस होटल प्रेजेंट इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड एवं किड्स रनवे शो का आयोजन एक रेस्टोरेंट में हुआ। इस शो को ली डिवाइन कम्पनी एंड ए स म्यूजिक रिकॉर्ड्स ने आयोजित किया। बच्चों का मेकअप आई के अकादमी द्वारा किया गया। वहीं अभिनेत्री संगीता बिजलानी के मेकअप में दीप्ति नंनवानी एमबीडी का बहुत बड़ा योगदान रहा। सेलिब्रिटी संगीता बिजलानी ने सभी बच्चों व अन्य को सम्मानित किया। आर्किटेक्चर कोप्पल खंडेलवाल को बेस्ट आर्किटेक्चर और बेस्ट कम्पनी के रूप में सम्मानित किया गया। शो में विशिष्ट अतिथि आगरा के प्रिंस गोयल रहे। जबकि कुलदीप आर्य, गोविंद सिंह रावत, गर्वित आर्य, अलीगढ़ से निक्की चंद्रिका, डॉ लक्ष्मी अनुराग, अनुज यादव, जीशान वसीम, मिलन वार्ष्णेय, ख्यालीराम मिठाई वाले आदि मौजूद रहे। पूनम कौशिक व श्रुति सरल अंकित शर्मा ने सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में इन सभी का बहुत बड़ा योगदान रहा।

नौ साल पहले दिल्ली निवासी युवक से मोबाइल लूट के मामले में आरोपितों को सजा

मुरादाबाद। मुरादाबाद जनपद की विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट कोर्ट सुरेंद्र कुमार की अदालत ने गुरुवार को 9 साल पहले दिल्ली निवासी युवक से चलती ट्रेन से मोबाइल लूट के मामले में मुख्य आरोपित को 6 साल 3 माह की सजा और दूसरे को 3 साल की सजा सुनाई। दोनों आरोपितों पर क्रमशः सात और दो हजार रुपए जुमार्ना भी लगाया। दिल्ली के इंदिरापुरी पश्चिमी निवासी मोहम्मद आदिल ने न्य मुरादाबाद के थाना जीआरपी में में दर्ज कराई प्राथमिकी में बताया था कि 12 जून 2016 को वह काठगोदाम से दिल्ली जा रहे थे उनका भाई ट्रेन के गेट पर बैठा हुआ था मुरादाबाद जनपद में सिरकोई भूड़ रेलवे क्रॉसिंग के पास लाइन के पास खड़े बदमाश ने रेलगाड़ी की रफ्तार धीमी होने के कारण उसका मोबाइल छीन लिया था।

मामले में जांच के बाद थाना जीआरपी पुलिस ने मुरादाबाद जनपद के थाना कुंदरकी क्षेत्र के चक फाजलपुर निवासी सरफराज उर्फ छोटू और महानगर के थाना मझोला क्षेत्र के काशीराम नगर निवासी मोहित उर्फ वांटेड को गिरफ्तार कर मोबाइल बरामद किया था। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट सुरेंद्र कुमार की अदालत में चली जिसमें न्यायालय ने को दोषी करार दिया। विशेष लोक अभियोजक एससी एसटी कोर्ट आनंदपाल सिंह ने बताया कि न्यायालय ने आज सरफराज को 6 साल तीन माह की सजा और 7000 जुमार्ना लगाया जबकि दूसरे आरोपित मोहित को 3 साल की सजा और 2000 जुर्माना लगाया।

कन्नौज: प्रभारी मंत्री ने बाढ़ पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री, कहा कोई कष्ट न हो

मनीषा

कन्नौज। बाढ़ प्रभावितों को किसी भी स्तर पर राहत कार्यों में लापरवाही न हो और जरूरतमंद लोगों की हर सम्भव मदद की जाए। उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा, राज्य मंत्री एवं जनपद की प्रभारी मंत्री रजनी तिवारी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कासिमपुर में राहत शिविर में 207 बाढ़ पीड़ितों निशुल्क राहत सामग्री वितरित की। राहत सामग्री में अरहर दाल 02 किलो, भुना चना 02 किलो, चना 02 किलो, चीनी 01 किलो0, आटा 10 किलो, चावल 10 किलो, नमक 01 किलो, सरसों का तेल/रिफाइण्ड 01 लीटर, हल्दी 200 ग्राम, मिर्च 100 ग्राम, सब्जी मसाला 200 ग्राम, बिस्कुट 10 पैकेट, माचिस 01 पैकेट, मोमबत्ती 01 पैकेट, 01 पीस नहाने का

साबुन दिया गया। इस दौरान उन्होंने ग्रामवासियों की समस्याएं सुनी। उन्होनें कहा कि प्रदेश की योगी सरकार बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़ी हैं, उनकी हर संभव मदद के लिये तत्पर्य हैं। मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर राहत कार्यों में लापरवाही न हो और जरूरतमंद लोगों की हर आवश्यक सहायता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि चिकित्सा टीमें पूरी सतर्कता के साथ कार्य करें, जलजनित रोगों की रोकथाम हेतु समुचित प्रयास हों, और यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी कहा कि पशुओं के लिये चारे, तथा ठहरने एवं पशु चिकित्सा की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए।

कहा कि जल स्तर के घटने पर अधिकतर बीमारियां फैलती हैं। स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य कैंप के साथ ही बेहतर चिकित्सीय सुविधा प्रदान करें। उन्होंने कहा कि राहत शिविर में साफ-सफाई, स्वच्छ पेयजल, भोजन और बिजली आपूर्ति जैसे बुनियादी जरूरतों पर विशेष ध्यान दिया जाये। राहत शिविरों में ठहरने की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। इस अवसर पर जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री, पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार, अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) आशीष कुमार सिंह, ज्वाइंट मजिस्टेट/उप जिलाधिकारी सदर वैशाली सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

चंद्रग्रहण के कारण विन्ध्यवासिनी मंदिर के कपाट समय से पहले होंगे बंद, आरती समय में भी बदलाव

मीरजापुर। रविवार देर रात लगने वाले चंद्रग्रहण को देखते हुए विश्वप्रसिद्ध मां विन्ध्यवासिनी मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए समय से पहले बंद कर दिए जाएंगे। विंध्य पंडा समाज के मंत्री भानु पाठक ने बताया कि रविवार रात 9:58 बजे से चंद्रग्रहण शुरू होकर देर रात 1:26 बजे समाप्त होगा। इसी वजह से मंदिर के कपाट ग्रहण काल में बंद रहेंगे। उन्होंने बताया कि सामान्यतः मां की बड़ी आरती रात 9:30 बजे से शुरू होकर कपाट आधी रात 12 बजे तक खुले रहते हैं। लेकिन ग्रहण के कारण रविवार को बड़ी आरती का समय बदलकर रात 8:45 बजे कर दिया गया है। 9:45 बजे तक आरती-पूजन सम्पन्न कर मां का शयन लगा दिया जाएगा और कपाट बंद कर दिए जाएंगे। अगले दिन प्रातःकाल मंगला आरती के बाद सुबह 5 बजे से कपाट पुनः श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे।

भारत रक्षा संघ का चौथा राष्ट्रीय अधिवेशन 5 से 7 सितंबर तक आगरा में..

आगरा

आगरा में 5 से 7 सितंबर तक भारत रक्षा संघ का चौथा राष्ट्रीय अधिवेशन 'हिंदू जागो- देश जगेगा' की थीम के साथ बाईपास स्थित गुरुद्वारा, गुरु का ताल पर आयोजित किया जा रहा है। इस अधिवेशन में पूरे देश से संगठन के करीब दो हजार प्रतिनिधि भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति और सांस्कृतिक जागरण के मुद्दों पर चिंतन और विचार विमर्श किया जायगा। संगठन के जिला अध्यक्ष रिंकू पाराशर द्वारा बताया गया कि भारत रक्षा मंच का आगरा में यह चौथा राष्ट्रीय अधिवेशन है इससे पूर्व नागपुर, भोपाल में ये अधिवेशन हो चुके हैं। भारत रक्षा मंच की नींव

राष्ट्रीय अस्मिता, संस्कृति और सुरक्षा की भावना से रखी गई है। मंच अपने स्थापना से ही निरंतर राष्ट्र विरोधी तत्वों, अवैध घुसपैठ और सांस्कृतिक हमले के विरुद्ध आवाज उठाता रहा है और हिंदुओं को जागरूक करने का काम कर रहा है। संगठन अपने प्रेणना वाक्य 'मुखर हिंदू प्रखर राष्ट्र' कि भावना के साथ राष्ट्रीय एकता, अखंडता और संप्रभुता बनाए रखने के लिए अपने कार्यक्रम चलाता है।

जिला अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि यह संगठन का आगरा में राष्ट्रीय स्तर का पहला कार्यक्रम है। हालांकि संगठन आगरा में सक्रिय है और अपने उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्यक्रम आयोजित करता रहता है।

रिंकू पाराशर ने बताया कि प्रस्तावित राष्ट्रीय अधिवेशन में 5 सितंबर को प्रदर्शनी का उद्घाटन उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य द्वारा किया जाएगा। इस दौरान प्रज्ञा ठाकुर की मौजूद रहेंगी. 6 सितंबर को कार्यक्रम के विधिवत उद्घाटन के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आमंत्रित किया गया है।

कार्यक्रम के दौरान अन्य महानुभावों की अतिरिक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यनारायण जटिया मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। आगरा में कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए श्रीनिवास गुप्ता बृज प्रांत संगठन मंत्री और राजीव गुप्ता जय राम मार्बल नेतृत्व में स्थानीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता जी जान से जुटे हुए हैं। बाहर से आए संगठन प्रतिनिधियों के ठहरने के लिए अधिकांश व्यवस्था गुरुद्वारा में ही की जा रही है,अन्य लोगों के लिए स्थानीय होटलो को बुक किया गया है।

Published, printed and owned by Rajesh.Chauhan, printed at B B Graphic printer Z--57 Okhla Industrial Area ph.2 New Delhi -110020 and published at BG 6 305 B Paschim Vihar New Delhi --110063 Editor Rajesh.Chauhan. E mail ID-rajeshchauhan4569@gmail.com, Contact No. - 9873104569, RNI No.- DLHIN/25/A2321